A Daily News Magazine
भोपाल
मंगलवार, 06 जनवरी, 2026

सुबह सवेरे

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 126, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

विधानसभा चुनाव बीजेपी से ज्यादा उसके चुनाव प्रबंधन का टेस्ट!

अरविंद मोहन

वैसे तो इस साल से ही सारे दलों की तरफ़ से चुनावी दाँवपेंच शुरू हो गए हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद होने वाले पाँच विधान सभाओं को जीतने में कोई कसर न रहे, लेकिन नया साल आते ही इन चुनावों का धूम धड़ाका शुरू हो जाएगा। चुनाव पहली छमाही में ही नहीं अप्रैल और मई से पहले हो जाएंगे। असम, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के लिए चुनाव मार्च-अप्रैल में होंगे तो तमिलनाडु और केरल विधान सभाओं के लिए अप्रैल-मई में। और निश्चित रूप से चुनाव का ज़्यादा शोर मचाने की वजह बीजेपी का मैदान में होना और प्रमुख खिलाड़ी रहना है। क़ायदे से वह एक राज्य में शासन में है और दूसरे में काफी पिछड़कर मुख्य विपक्ष है। पर एक राज्य, पुदुचेरी में उसने जिस तरह बिना एक भी विधायक जिताए सरकार बना लिया वह उसकी राजनैतिक लड़ाई लड़ने का तरीक़ा है। और अगर अभी के चुनाव को लेकर अभी से गरमाहट आ गई है तो यह बीजेपी के चुनाव लड़ने का तरीक़ा है जो नगर पालिका चुनाव तक को नरेंद्र मोदी और अमित शाह की प्रतिष्ठा से जोड़ देती है।

और इसे किसी दोष की तरह देखने की ज़रूरत नहीं है। आज बीजेपी का जो एकछत्र राज बना है, अन्य दलों से वह जिस तरह आगे निकली है उसमें उसके चुनाव लड़ने के तरीके, साधनों की भरमार और साल के 365 दिन की तैयारी का बड़ा हाथ है। और अन्य राज्यों के मुक़ाबले पश्चिम बंगाल में यह सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी इसे जीतने के लिए काफी बेचैन है। दो लोक सभा और दो विधान सभाओं में तृणमूल कांग्रेस को मुख्य टक्कर देने के बाद उसे लग रहा है कि 15 साल के ममता राज से लोगों की जो नाराजगी बढ़ी है उसका लाभ लेकर वह इस बार बंगाल का किला फतह कर सकती है।

पर उसकी मुश्किल यह है कि उसके पक्ष में 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से जो वेग बना था, वह उतार पर आता दिखने लगा है। उसका वोट प्रतिशत गिरा है और तृणमूल का बढ़ा है। साथ ही उसके सांसद और विधायक भी कम चुने गए हैं। दलबदल में भी अब मौकापरस्त या किसी दबाव में उसकी तरफ आने वालों की रफ्तार कम हुई है।

बीजेपी की दिक्कत बंगाली समाज के बारे में बनी उसकी दोषपूर्ण राय और बंगाली समाज के भद्रलोक द्वारा उसके तौर तरीकों को नापसंद करने से जुड़ी है। इसके साथ ही वहां के लगभग एक चौथाई मुसलमान मतदाता भी अब पूरी तरह तृणमूल के साथ आ गए हैं। पहले कांग्रेस और वाम दलों को भी यह वोट मिलता था। बीजेपी ने एक बार हिन्दू मुसलमान ध्रुवीकरण कर तो दोबारा नामशूद्रों की गोलबंदी करके सफलता पानी चाही जो आंशिक रूप में ही सफल हुई। बंगाल में समाज सुधार आंदोलनों के चलते जाति और संप्रदाय की गोलबंदी कम है। और समाज पर प्रभावी भद्रलोक में बीजेपी की घुसपैठ नहीं है। इस बार बीजेपी ने एक युवा कायस्थ नितिन नबीन को अपना अध्यक्ष चुनकर कुछ अलग संकेत देने की कोशिश की है, लेकिन इससे पहले पंचायत चुनाव में बड़ी संख्या में मुसलमान उम्मीदवार उतारने का उसका दांव पिट गया है।

बीजेपी की मुश्किल कांग्रेस और वाम दलों के एकदम पस्त होने से भी बढ़ी है जिनका वोट उसकी तरफ़ आने के ज़्यादा तृणमूल की तरफ़ गया है। दो चुनावों में भाजपा का वोट प्रतिशत सिर्फ डेढ़ फीसदी बढ़ा तो तृणमूल ने तीन फीसदी ज्यादा वोट पा लिए हैं।

असम में भी बीजेपी की परेशानी दस साल शासन करने और नागरिकता या घुसपैठ जैसे किसी मुद्दे पर ज़्यादा कुछ न कर पाने से जुड़ी है। उधर, कांग्रेस ने जब से मौलाना बदरुद्दीन वाली मुसलमानों की पार्टी से रिश्ता तोड़ा है उसे मुसलमानों का भरपूर वोट तो मिला ही है, बीजेपी के लिए उस पर हमला करना और चुनाव को हिंदु-मुसलमान बनाना मुश्किल हुआ है। राज्य में सीटों का अंतर काफी है (हालाँकि उसमें भी बीजेपी कुछ कम हुई है) लेकिन वोट प्रतिशत की लड़ाई बराबरी वाली हो गई है। और इस बार बीजेपी को ज़्यादा परेशानी अहोम सर्बानंद सोनोवाल को हटाकर पंडित हेमंत बिसवा सरमा को मुख्यमंत्री बनाने से भी जुड़ी है।

सरमा प्रशासनिक रूप से कुशल हैं पर आसामी समाज में शासक रहे अहोम समाज को सत्ता जाने का मलाल है। असम में बहुत क़िस्म की अस्मिताएँ-पहचान काम करते हैं लेकिन नागरिकता, सीएए, पॉपुलेशन रजिस्टर, जनगणना और गहन मतदाता सर्वेक्षण जैसे किसी भी सवाल पर स्पष्ट फैसला न लेना और कोई नतीजा न देना, भाजपा को परेशान करेगा। पर जिस तरह बीजेपी चुनाव लड़ती है वैसा और कोई नहीं लड़ता यह सच्चाई भी याद रखनी होगी।

तमिलनाडु के चुनाव में बीजेपी ही नहीं, पूरा विपक्ष अभी पहले से कमजोर लग रहा है। अन्नाद्रमुक में टूट और बीजेपी का उससे छिटकना ही नहीं, वन्नीयारों वाली पार्टी पीएमके और अभिनेता विजयकान्त की गवांडीयरों वाली पार्टी अभी हाथ पाँव ही मार रही है। अन्नाद्रमुक से निकले थेवर नेता पन्नीरसेलवम और दिनाकरण भी अभी ठिकाना नहीं पा सके हैं। उधर द्रमुक, कांग्रेस और वाम दलों का गठबंधन हर तरह से मज़बूत और एकजुट दिख रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि विपक्षी गठजोड़ बन भी जाए तो एम स्टालिन को हराने लायक दम जुटाना मुमकिन नहीं है।

केरल को लेकर बीजेपी ज़रूर इस बार उत्साहित है। हालाँकि वहां भी लोकसभा चुनाव में वह शून्य पर ही आ गई थी। लेकिन उसे ठीक ठाक वोट मिले हैं और अभी त्रिवेंद्रम की स्थानीत सरकार पर उसके कब्जे से उसका उत्साह बढ़ा है। पर बहुत साफ़ जातिगत और सांप्रदायिक गोलबंदी वाले केरल समाज में बीजेपी कुल मिलाकर हिन्दू नायरों और कुछ असंबद्ध युवकों को ही आकर्षित कर पाई है। और यह वोट जितना बढ़ेगा दस साल से शासन कर रही वाम मोर्चा सरकार की परेशानियां बढ़ेंगी क्योंकि बीजेपी के लिए ईसाई और मुसलमान वोट पाना संभव नहीं है। यह स्थिति कांग्रेस के लिए अच्छी बन जाती है, जिसके पास ज्यादा कुछ नहीं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के यहां से चुनाव लड़ने के चलते आया उत्साह भर है।

बीस लाख से कम आबादी वाले पुदुचेरी की आबादी का संतुलन बहुत नाजुक है और जिस तरह पिछली बार बीजेपी ने वहां मनोनयन वाले तीन विधायकों और राज्यपाल के सहारे सरकार बना ली उससे नाराजगी है।

इसलिए विधानसभा के सभी पाँच राज्यों में बीजेपी के लिए बहुत उत्साह वाली कोई चीज नहीं दिखती, लेकिन ऐसी स्थिति बनाना और जश्न मनाना उसे आता है।

(सत्य हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

शरद की सुबह

आम भारतीय स्त्रियों!
तुम कौन हो?
तुम कहाँ से आई हो?
तुम इतनी श्रद्धा
इतना विश्वास
इतना प्रेम
इतनी करुणा क्यों हो?
तुम कभी कहीं लुप्त तो नहीं
जाओगी?
भारत!
मेरे प्रिय भारत!
न्यू ईयर पर
शराब पीकर घर लौटी अपनी
बच्ची को
जो दुर्भाग्यशाली स्त्री छीटे मार कर
जगा रही है -
ऐसी ही किसी स्त्री का
बेटा बनाना मुझे
हर जन्म में हर बार!

- मनमीत सोनी

'हाड़' कंपाने वाली सर्दी, कोहरे का 'आतंक'

आगरा-मुजफ्फरनगर में 9 गाड़ियां टकराईं, 5 की मौत

नई दिल्ली (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी राज्यों में ठंड बढ़ गई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में शीतलहर के साथ घना कोहरा छाया है। सोमवार सुबह मध्य प्रदेश में इस सीजन का सबसे घना कोहरा रहा। एमपी की राजधानी भोपाल में विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम रही। राज्य के 20 जिलों में स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। भोपाल और धार में ठंड के चलते स्कूलों का समय सुबह 9.30 बजे से कर दिया गया है। यूपी में कोहरे के कारण सोमवार को मुजफ्फरनगर और आगरा में सड़क हादसों में 9 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इनमें 5 लोगों की मौत हुई, जबकि 10 से ज्यादा घायल हैं। लखनऊ समेत 10 शहरों में बादल छाए हैं और 10-15 किमी/घंटा की रफ्तार से सर्द हवाएं चल रही हैं। लद्दाख के लेह में सोमवार को भारी बर्फबारी के कारण सभी फ्लाइट ऑपरेशन अस्थायी रूप से रोक दिए गए। पिछले 24 घंटों में 0.6 सेमी बर्फबारी हुई, जबकि न्यूनतम तापमान -9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यहां रोजाना 10-15 फ्लाइट्स आती-जाती हैं। राजस्थान में रविवार को सीजन की सबसे सर्द दिन-रात रहे। माउंट आबू में तीसरे दिन भी तापमान शून्य रहा, जबकि सात शहरों में रात का पारा 5 डिग्री से नीचे दर्ज रहा।

उत्तराखंड में 7 शहरों में पारा शून्य से नीचे

उत्तराखंड में कड़ाके की सर्दी के बीच रविवार को पिथौरागढ़ जिले का मुनस्यारी सबसे ठंडा इलाका रिकॉर्ड किया गया है। यहां न्यूनतम तापमान माइनस 25 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। इसके अलावा 7 अन्य शहरों में तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया। चमोली के आली बिनानी बुग्याल में सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई। मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को 5 जिलों- उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। बिहार की राजधानी पटना समेत सभी जिलों में भीषण सर्दी और घने कोहरे का असर जारी है। राज्यभर में 12 से 15 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से सर्द हवाएं चल रही हैं।

इंदौर के बाद गांधीनगर में दूषित पानी, 104 बच्चे बीमार

- अस्पताल में नए वार्ड खोलने पड़े, पाइप लाइन में लीकेज से पानी में सीवेज की गंदगी मिली

गांधी नगर (एजेंसी)। इंदौर के बाद अब गुजरात की राजधानी गांधीनगर में गंदा पानी पीने से पिछले तीन दिनों 104 बच्चे 150 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। इनमें से 50 फीसदी बच्चों को टाइफाइड हुआ है। हालात इतने बिगड़े कि सिविल अस्पताल में बच्चों भर्ती करने के लिए नया वार्ड खोलना पड़ा। इंदौर की तरह यहां भी पीने के पानी की पाइप लाइन में सीवेज की गंदगी मिल रही थी। शहर के सेक्टर-24, 28 और आदिवाड़ा इलाके के लोग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। प्रशासन ने पानी की सप्लाई जांची तो 10 जगह लीकेज मिले। स्मार्ट सिटी योजना के तहत करोड़ों की लागत से बिछाई गई नई पाइपलाइन में यह लीकेज थे। हालात की गंभीरता को देखते हुए 75 स्वास्थ्य टीमें तैनात की गई हैं, जो 90 हजार लोगों की जांच कर चुकी हैं। गृह मंत्री अमित शाह और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने भी मामले का संज्ञान लिया है। डॉक्टरों ने आशंका जताई है कि 20 जनवरी तक मामलों की संख्या 350 का आंकड़ा पार कर जाएगी।

जयपुर में हुआ राजस्थान डिजीफेस्ट-टाई ग्लोबल समिट-2026

देश का सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट है मप्र: मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश, देश का सबसे युवा राज्य है। मध्यप्रदेश टाइगर स्टेट है, चीता स्टेट है, फारेस्ट स्टेट है, मिनरल स्टेट है, बिजली सरप्लस स्टेट है और अब देश का सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट भी बन गया है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश वर्ष 2025 में सबसे ज्यादा निवेश पाने वाला देश का तीसरा राज्य बना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश अनंत अवसर और संभावनायें लिए हुए है। मध्यप्रदेश में निवेश हर मायने में लाभ का सौदा है। देश के मध्य में होने के कारण मध्यप्रदेश व्यापार, व्यवसाय, उद्योग-धंधे और स्टार्ट-अप्स लगाने से लेकर अपने उत्पाद को निर्यात करने के लिए एक अनुपम केंद्र बन रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को पिंक सिटी जयपुर में राजस्थान डिजीफेस्ट-टाई ग्लोबल समिट 2026 में मध्यप्रदेश सेशन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश और राजस्थान दोनों सदियों से इतिहास, विरासत और व्यापार-व्यवसाय की समझ के मामले में साझा भागीदार रहे हैं। राजस्थान के मारवाड़ी व्यापारी मध्यप्रदेश में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। समिट में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा भी उपस्थित थे। मध्यप्रदेश सरकार इस प्रतिष्ठित ग्लोबल समिट में 'स्टेट पार्टनर' के रूप में सहभागिता कर रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश को विकास और अवसरों का केंद्र बताते हुए निवेशकों और उद्योगपतियों से कहा कि हमारा प्रदेश आज देश के उन चुनिंदा राज्यों में है, जहां प्राकृतिक संसाधन, उद्योग-अनुकूल नीतियां, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और सहयोगी सरकार सभी निवेशकों के लिए आदर्श वातावरण तैयार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में 18 नई उद्योग-अनुकूल नीतियां, विस्तृत लैंड बैंक, भरपूर जल उपलब्धता, स्किल्ड मानव

- **देश के दिल से जुड़ें, मध्यप्रदेश है अनंत संभावनाओं का केंद्र**
- **हम निवेशकों के लिए तैयार कर रहे हैं आदर्श वातावरण**

संसाधन, उत्कृष्ट लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी और पारदर्शी प्रशासन निवेशकों को सर्वोत्तम सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉ. यादव एवं अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्ज्वलित कर राजस्थान डिजिफेस्ट-टाई ग्लोबल समिट के मध्यप्रदेश सेशन का विधिवत् शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि सभी राज्यों के बीच औद्योगिक विकास की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा चल रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में देश के सभी राज्यों को आगे बढ़ने का समान अवसर मिल रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था आज भी उहापोह की स्थिति में है, ऐसी परिस्थिति में भी भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। भारत के लोकतंत्र में 'जियो और जीने दो' की भावना समाहित है। उद्योग-व्यापार से कई लोगों के जीवन में सवेरा आता है। इससे पवित्र काम कुछ नहीं हो सकता है। मध्यप्रदेश विकास के सभी सेक्टर्स में लगातार आगे बढ़ रहा है। प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर भी कई बड़े पुरस्कार मिले हैं। हमारे टूरिज्म सेक्टर में सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। पिछले दो साल में हमने प्रदेश में दो नए टाइगर रिजर्व बनाए हैं। मध्यप्रदेश टाइगर और वल्चर स्टेट तो है ही, हमारी धरती पर चीता भी तेजी से अपना कुनबा बढ़ा रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश नदियों का मायका है। यहां 250 से अधिक नदियां बहती हैं। हमने राजस्थान के साथ जल बंटवारे का विवाद सुलझाया। हमारे कार्यों में परस्पर सौहार्द्र और बंधुता का भाव होना चाहिए।

पहली बार महाभारत समागम का आयोजन भारत भवन में 16 से 24 तक

भोपाल। वैश्विक सभ्यताओं के संघर्ष और औदार्य की महागाथा महाभारत पर केन्द्रित देश का पहला और अब तक का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन भोपाल के भारत भवन में 16 से 24 जनवरी तक वीर भारत न्यास द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस नौ दिवसीय समागम में महाभारत के विभिन्न आयामों को लेकर नाटक, नृत्य-नाट्य, कठपुतली कार्यशाला, लोक एवं शास्त्रीय प्रस्तुतियाँ, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, इमर्सिव डोम थियेटर के माध्यम से युद्ध के खिलाफ शांति का संदेश दिया जायेगा। इस अवसर पर प्रदर्शनी नेपथ्य, अस्त्र-शस्त्र, चक्रव्यूह एवं पताकाएँ, महाभारत आधारित चित्र प्रदर्शनी, भारतीय कठपुतली तथा प्रकाशनों सभ्यताओं की साँस (वैश्विक कविताओं का संकलन), भूली बिसरी सभ्यताएँ पुस्तकों का लोकार्पण भी होगा।

- **सभ्यताओं के संघर्ष एवं औदार्य की महागाथा**

वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव श्रीराम तिवारी ने बताया कि आज रूस, चीन, अमेरिका, यूक्रेन, ईरान, इराक, वेनेजुएला, क्यूबा, बांग्लोदश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान सहित पूरी दुनिया युद्ध, हिंसा और टूटती सभ्यताओं की पीडा से गुजर रही है, ऐसे समय में महाभारत हमें आत्ममंथन और शांति का मार्ग दिखाता है। सभ्यताओं के संघर्ष और औदार्य की इस महागाथा में युद्ध की अनिवार्यता के साथ-साथ उसके दुष्परिणामों का भी गहन बोध है। न्यासी सचिव ने कहा कि वास्तव में श्रीकृष्ण ने महाभारत युद्ध को रोकने के लिए अपने जीवन के सर्वाधिक गंभीर और करुण प्रयास किए। उन्होंने बल नहीं, बल्कि संवाद को प्राथमिकता दी; अस्त्र नहीं, बल्कि विवेक को आगे रखा। शांति-दूत बनकर वे हस्तिनापुर गए और कौरवों से केवल पाँच गाँव माँगकर यह सिद्ध किया कि धर्म का मार्ग त्याग और सहमति से होकर जाता है। श्रीकृष्ण का संदेश आज के समय में और भी प्रासंगिक है।

वे सिखाते हैं कि युद्ध कभी पहली पसंद नहीं होनी चाहिए, और जब संघर्ष अनिवार्य हो जाए, तब भी उसका उद्देश्य विनाश नहीं, बल्कि न्याय और लोककल्याण होना चाहिए। महाभारत में श्रीकृष्ण का प्रयास मानवता के लिए शांति, संवाद और विवेक की अमर सीख है। उन्होंने बताया कि महाभारत युद्ध में 185 से अधिक जनजातियाँ शामिल थीं।

इसी भावभूमि पर केन्द्रित देश का पहला और अब तक का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन भोपाल के भारत भवन में 16 से 24 जनवरी 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। समागम का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्रीजी डॉ. मोहन यादव द्वारा किया जायेगा। अन्य कार्यक्रमों में माननीय मंत्रीगण मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किये जा रहे है। वीर भारत न्यास द्वारा आयोजित यह आयोजन महाभारत को केवल युद्ध कथा के रूप में नहीं, बल्कि शांति, करुणा और सभ्यतागत विवेक के महाकाव्य के रूप में प्रस्तुत करेगा।

न्यासी सचिव ने कहा कि वैश्विक सभ्यताओं का इतिहास संघर्ष और औदार्य की साझा गाथा है। संघर्ष ने उन्हें दृढ़ता, साहस और पहचान दी, जबकि औदार्य ने सहअस्तित्व, करुणा और संवाद सिखाया। टकराव के बीच भी संस्कृतियाँ एक-दूसरे से सीखती रहीं और मानवता को आगे बढ़ाया। इसी उद्देश्य से भारत के साथ इंडोनेशिया, श्रीलंका, जापान के प्रतिष्ठित नाट्य समूह अपनी-अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। श्रीराम तिवारी ने कहा कि वीर भारत न्यास के उद्देश्यों के अनुरूप आने वाले वर्षों में इस समागम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विस्तार किया जायेगा।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 25 °c

न्यूनतम 22°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ मंगलवार, 06 जनवरी 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर हुआ हमला

● कई खिड़कियों के शीशे टूटे ,पुलिस ने एक को पकड़ा

वॉशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के ओहायो वाले घर पर हमला हुआ है। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इस मामले की जांच जारी है। पुलिस ने बताया कि हमले के वक्त उपराष्ट्रपति वेंस का परिवार घर पर नहीं था। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार,

अधिकारियों का मानना है कि हमलावर व्यक्ति उपराष्ट्रपति के घर में नहीं घुसा था। स्थानीय समाचार आउटलेट्स की तस्वीरों में जेडी वेंस के घर की खिड़कियों को नुकसान पहुंचा हुआ दिखा, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में क्या हुआ था। अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि वेंस को कौन निशाना बना रहा था।

मृत्यु या विनाश... अर्थव्यवस्था खतरे में डालना भी हिंसा

● सुप्रीम कोर्ट ने उमर-शरजील मामले में दिया बड़ा फैसला ● जमानत नहीं देने के साथ ही बढ़ा दिया 'यूएपीए' का दायरा

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिन पर 2020 के दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत अपराधों का आरोप है। हालांकि, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने पांच अन्य आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, शादाब अहमद और मोहम्मद सलीम खान को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि हर आरोपी की जमानत याचिका की अलग-अलग जांच की जानी चाहिए क्योंकि सातों आरोपी अपराध के मामले में समान नहीं

हैं। बेंच ने कहा-उमर खालिद और शरजील इमाम अन्य आरोपियों की तुलना में गुणात्मक रूप से अलग स्थिति में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में यूएपीए की बड़ी व्याख्या भी कर दी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा-एक साल बाद फिर से करें अपील

कोर्ट ने फैसला सुनाया कि रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों से खालिद और इमाम के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। खालिद और इमाम के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे संरक्षित गवाहों की जांच के बाद या आज से एक वर्ष बाद अपनी जमानत याचिकाएं फिर से दाखिल कर सकते हैं। न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष की सामग्री से प्रथम दृष्टया एक केंद्रीय और निर्णायक भूमिका और घटनास्थलीय और स्थानीय कृत्यों से परे योजना, लामबंदी और रणनीतिक दिशा के स्तर पर संलिप्तता का पता चलता है।

धारा 15 की व्याख्या हिंसा तक सीमित नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अगर अपील स्वीकार की जाती है तो पीठ को यह निर्धारित करने के लिए एक व्यवस्थित जांच करनी होगी कि क्या अभियोजन सामग्री प्रथम दृष्टया मामला बनता है और क्या आरोपी को सौंपी गई विशिष्ट भूमिका वैधानिक सीमा को पार करती है। निर्णय में आगे कहा गया कि आतंकवादी कृत्यों से संबंधित अपराध के लिए दंडात्मक अधिनियम (यूएपीए) की धारा 15 की संकीर्ण व्याख्या केवल स्पष्ट हिंसा के कृत्यों तक सीमित नहीं की जा सकती। मृत्यु या विनाश के अलावा, यह प्रावधान उन कृत्यों को भी शामिल करता है जो सेवाओं को बाधित करते हैं और अर्थव्यवस्था को खतरे में डालते हैं। पीठ ने कहा- हालांकि, इन अपीलकर्ताओं द्वारा भुगती गई कारावास की अवधि काफी लंबी है और इस पर पूरी तरह से विचार किया गया।

सुनवाई में देरी को ट्रंप कार्ड नहीं बना सकते

पीठ ने कहा- यूएपीए की धारा 43डी(5) के तहत सीमा लागू होती है...निरंतर हिरासत ने उनके खिलाफ वैधानिक प्रतिबंध को रद्द करने के लिए संवैधानिक अस्वीकार्यता को पार नहीं किया है। जस्टिस अरविंद कुमार ने फैसला सुनाते हुए कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत अभियोगों में, मुकदमे की सुनवाई में देरी को 'ट्रंप कार्ड' के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है जो स्वत: ही वैधानिक सुरक्षा उपायों को निरस्त कर दे। साथ ही, न्यायालय ने यह भी कहा कि यूएपीए की धारा 43डी(5) प्रथम दृष्टया मामले की पुष्टि के लिए न्यायिक जांच को पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं करती है। न्यायिक जांच आरोपी-विशिष्ट होती है।

ट्रम्प ने वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति को दी धमकी

● ट्रंप ने कहा-हमारी बात नहीं मानी तो और बुरा हाल करेंगे

वॉशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज को बुरा हाल करने की धमकी दी है। ट्रम्प ने कहा,अगर डेल्सी वह नहीं करतीं जो वेनेजुएला के लिए अमेरिका सही मानता है, तो उनका हाल

मादुरो से भी ज्यादा बुरा हो सकता है। ट्रम्प ने यह बात द अटलांटिक मैग्जीन को दिए इंटरव्यू में कही है। इससे पहले न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए इंटरव्यू में ट्रम्प ने कहा था अगर रोड्रिग्ज अमेरिका की बात मान लेती हैं तो वेनेजुएला में अमेरिकी सेना तैनात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं, रोड्रिग्ज ने मादुरो को सत्ता से हटाने की आलोचना की है। साथ ही मादुरो को वापस भेजने की मांग की है।

मैनपावर भर्ती के लिए आवश्यक औपचारिकताएं समय से करें पूर्ण : उप मुख्यमंत्री शुक्ल

भोपाल। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की विस्तृत समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने बैठक में उपकरणों की खरीदी समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही पीएम-अभीम, 15वें वित्त आयोग की राशि और राज्य बजट का निर्धारित समय-सीमा में उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग एवं विधि विभाग से सतत संपर्क में रहकर मैनपावर भर्ती से संबंधित अग्रेषित प्रकरणों पर तत्परता से कार्यवाही के निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने शासकीय मेडिकल कॉलेजों में ट्यूटर/डिमॉन्स्ट्रेटर पदों पर नियमित भर्ती के निर्देश दिए। साथ ही मेडिकल कॉलेजों के अंतर्गत संचालित नर्सिंग कॉलेजों के नर्सिंग शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के लिए सामान्य प्रशासन विभाग से शीघ्र अभिमत प्राप्त करने के लिए नियमित संपर्क में रह आवश्यक औपचारिकताओं की प्राथमिकता से पूर्ति के निर्देश दिए। अस्पताल सहायक के लगभग 1200 पदों और 1260 नर्सिंग पदों की भर्ती से संबंधित विषय जो कि वर्तमान में विधि विभाग में लंबित हैं, उनकी अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने एयर एम्बुलेंस के संचालन की समीक्षा की और विधिवत संचालन के लिए नियमित निगरानी के निर्देश दिए। बताया गया कि मेडिकल कॉलेजों में 843 और स्वास्थ्य विभाग के नर्सिंग कॉलेजों के लिए 286 नर्सिंग ऑफिसर पदों की भर्ती के लिए मांग पत्र कर्मचारी चयन मंडल को भेजा जा चुका है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने स्वास्थ्य विभाग के नर्सिंग कॉलेजों के नर्सिंग शिक्षकों के 59 राजपत्रित पदों की भर्ती के लिए मांग पत्र लोक सेवा आयोग को शीघ्र प्रेषित करने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा संदीप यादव, एमडी एमपीएचएसएल मयंक अग्रवाल सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

स्वास्थ्य विभाग के अग्रेषित विषयों पर प्राथमिकता से करें कार्यवाही

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित उन प्रस्तावों की समीक्षा की, जिन्हें अभिमत के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अग्रेषित किया गया है। उन्होंने अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग श्री संजय कुमार शुक्ला से चर्चा कर संबंधित प्रकरणों पर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि विषयों पर त्वरित रूप से अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

फर्जी डॉक्टर बनकर बुजुर्ग एवं बीमार व्यक्तियों से ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश

भोपाल। थाना देहात पुलिस नर्मदापुरम ने बीमारी ठीक करने का झांसा देकर बुजुर्ग एवं बीमार व्यक्तियों से ठगी करने वाले एक शातिर अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

दिनांक 13-14 दिसंबर 2025 को अज्ञात आरोपियों द्वारा फरियादी, निवासी नर्मदापुरम से संपर्क कर स्वयं को परिचित बताते हुए बीमारी ठीक करने की गारंटी दी गई थी। आरोपियों ने कथित डॉक्टर का मोबाइल नंबर देकर संपर्क करवाया। फोन पर बातचीत के दौरान घर आकर जांच व इलाज करने का आश्वासन दिया गया। अगले दिन आरोपी स्वयं को डॉ. बताते हुए एक साथी के साथ फरियादी के घर पहुंचे, बीमारी की जांच कर 'पेटेंट फार्मूला' की महंगी दवा से पूर्ण आराम होने का झांसा दिया तथा मोबाइल पर क्यूआर कोड दिखाकर 1 लाख रूपए की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर करवा ली। इसके बाद 'दवा गाड़ी में रखी है' कहकर दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना देहात नर्मदापुरम में अपराध बीएनएस के

अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक श्री साई कृष्णा एस. थोटा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक राजन तथा एसडीओपी नर्मदापुरम श्री जितेंद्र कुमार पाठक के मार्गदर्शन में थाना देहात/कोतवाली पुलिस की टीम गठित की गई।

टीम ने विवेचना के दौरान आरोपियों द्वारा उपयोग किए गए मोबाइल नंबर, बैंक खातों, सीसीटीवी फुटेज एवं वाहन के आधार पर तकनीकी साक्ष्य जुटाए। जांच में पाया गया कि ठगी की राशि राजस्थान में एटीएम के माध्यम से निकाली गई है। सीसीटीवी फुटेज एवं हुलिये के आधार पर पुलिस टीम ने साधारण वेशभूषा में भोपाल के आसपास एवं राजस्थान के घुम्मकड़ डेरों के क्षेत्रों में तलाश की। इस दौरान घटना में प्रयुक्त वाहन के साथ संदेही दो व्यक्तियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में 50 वर्ष से अधिक उम्र के बीमार व्यक्तियों से संपर्क कर स्वयं को परिचित बताते हैं, फिर तथाकथित डॉक्टर से मोबाइल पर बात कराकर इलाज का भरोसा दिलाते हैं।

2026 के लिए भारतीय सेना का रोडमैप तैयार

● शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म में हो रही बड़ी प्लानिंग

नई दिल्ली (एजेंसी)। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के साथ 88 घंटे की जंग के विश्लेषण के बाद सेना ने अहम बदलावों की रूपरेखा तैयार की है। सेना ने इसे तीन हिस्सों अल्पकालिक (शॉर्ट

टर्म), मध्यकालिक (मीडियम टर्म) और दीर्घकालिक (लॉन्ग टर्म) रणनीति में बांटा है। अल्पकालिक रणनीति के तहत 2026 का स्पष्ट रोडमैप बनाया गया है। सेना के सूत्रों ने बताया कि इस साल पूरा जोर हथियार हासिल करने की बजाए युद्ध के पूरे वातावरण की त्वरित जानकारी, नेटवर्क और तेज फैसलों पर केंद्रित रहेगा जो ऑपरेशन सिंदूर का अहम सबक है।

जयपुर में पहली बार जनता के बीच आर्मी की हुई परेड

● रोबोट डॉग्स से लड़ाकू विमान तक सब कुछ रहा शामिल

जयपुर (एजेंसी)। अगर आप इंडियन आर्मी को नजदीक से देखना और जानना चाहते हैं, तो आपके लिए यह एक सुनहरा अवसर है। 15 जनवरी को आर्मी डे के मौके पर पहली बार जनता के बीच आर्मी परेड आयोजित होने जा रही है। जयपुर के जगतपुरा क्षेत्र में होने वाली इस परेड में सेना की टुकड़ियों के साथ कई लड़ाकू विमान और रोबोट डॉग भी शामिल होंगे। जयपुर के नागरिकों सहित प्रदेश के लाखों लोग पहली बार सेना के अदम्य साहस और अनुशासन को नजदीक से देख सकेंगे। इन दिनों परेड की रिहर्सल चल रही है। रिहर्सल देखने के लिए भी लोगों की

भीड़ उमड़ रही है। जयपुर के जगतपुरा स्थित महल रोड पर परेड का आयोजन किया जाएगा। करीब साढ़े तीन किलोमीटर लंबी इस परेड की तैयारी को लेकर सेना के जवान नियमित रूप से रिहर्सल कर रहे हैं। आधा दर्जन से ज्यादा टुकड़ियां सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक अभ्यास करती हैं। सेना के जवानों के साथ रोबोट डॉग्स से भी रिहर्सल कराई जा रही है। परेड और रिहर्सल को देखते हुए जयपुर ट्रैफिक पुलिस की ओर से यातायात में व्यापक बदलाव किए गए हैं।

पीएम मोदी से मिले सीएम योगी

यूपी में मंत्रिमंडल फेरबदल पर चर्चा हुई तेज

लखनऊ (एजेंसी)। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे पर हर किसी की नजर है। सोमवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 45 मिनट तक बातचीत होती रही। सूत्रों का कहना है कि यूपी मंत्रिमंडल विस्तार, एसआईआर अभियान समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। योगी आदित्यनाथ गृहमंत्री अमित शाह से भी मिले। सीएम योगी आदित्यनाथ शाम को बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन और वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। सीएम के साथ यूपी के दोनों डिप्टी सीएम बृजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। नितिन नबीन के साथ होने वाली बैठक को यूपी संगठन में संभावित बदलावों से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी नेतृत्व आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए संगठन को और मजबूत करने की दिशा में बड़े फैसले ले सकता है। इसके तहत जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के साथ-साथ नए नेतृत्व को आगे लाने पर भी विचार हो सकता है।

जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की तैयारी

कैबिनेट विस्तार और कई मंत्रियों के फेरबदल के संकेतों ने चुनावी तैयारियों को संकेत देना शुरू कर दिया है। पार्टी अब नए साल में पूरी तरह से चुनावी मोड में उतरने वाली है। ऐसे में सभी जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद योगी कैबिनेट में विस्तार हो सकता है। पूर्व यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को मंत्री बनाया जा सकता है। योगी की मोदी और पाठक की नितिन नबीन-बीएल संतोष से मुलाकात के बाद यूपी में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। योगी सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। योगी सरकार 2.0 का पहला मंत्रिमंडल विस्तार लोकसभा चुनाव के समय हुआ था।

असम के मोर्चे में प्रियंका, अब होगी असली परीक्षा !

पहली बार होगा बीजेपी के सफल चाणक्य से सीधा मुकाबला

गुवाहाटी (एजेंसी)। साल 2026 में केंद्र शासित पुडुचेरी के साथ चारा राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम शामिल हैं। इन राज्यों में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या अगर जोड़ दें तो यह 824 पहुंच जाती है। बंगाल चुनावों के हाईवोल्टेज होने की संभावना के बीच कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को असम के मोर्चे पर उतारकर पूर्वोत्तर के इस राज्य को चर्चा में ला दिया है। केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद ऐसा पहली बार होगा जब किसी राज्य में बीजेपी के चाणक्य

और गृह मंत्री अमित शाह का प्रियंका गांधी से आमना-सामना होगा। असम में रणनीति बनाने का दायित्व गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में ही है। बीजेपी के द्वारा मौजूदा सीएम हिमंता बिस्वा सरमा के चेहरे के साथ ही चुनाव में जाने की उम्मीद है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने गौरव गोगोई को आगे किया है।

प्रियंका बनीं स्क्रीनिंग कमेटी की प्रमुख- कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को ऐसे वक्त पर आगे किया है जब बिहार चुनाव नतीजों के बाद उन्हें कमान सौंपने की आवाजें उठी थीं, हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के इस फैसले पर चुटकी लेते हुए कहा है कि कांग्रेस में सब ठीक नहीं है।

पहली बार होगा सीधा मुकाबला

असम में प्रियंका गांधी और अमित शाह रणनीतिकार के तौर आमने-सामने होंगे। अमित शाह लगातार हर राज्य की चुनावी रणनीति बनाते हैं। दिल्ली की चुनावी रणनीति भी अमित शाह ने ही बनाई थी। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के मजबूत किले को ध्वस्त कर दिया था। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की मजबूत उपस्थिति के बावजूद वहां की चुनावी रणनीति में भी अमित शाह का पूरा दखल रहता है। हाल में संपन्न हुए बिहार चुनावों में बीजेपी के सबसे बड़ी पार्टी बनने और एनडीए की प्रचंड जीत का श्रेय भी अमित शाह को मिला था।

जीविका दीदी की रसोई अब बस अड्डों पर भी मचाएगी धमाल

पटना (एजेंसी)। अब बिहार के बस डिपो सिर्फ आने-जाने की जगह नहीं रहेंगे, बल्कि यहां यात्रियों को घर जैसा सस्ता और पौष्टिक भोजन भी मिलेगा। राज्य के 19 प्रमुख बस डिपो में जल्द ही 'जीविका दीदी की रसोई' की शुरुआत होने जा रही है। यह पहल न केवल यात्रियों और चालकों की वर्षों पुरानी परेशानी दूर करेगी, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता का एक नया रास्ता भी खोलेगी। दरअसल, हाल ही में परिवहन सह ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कुछ बस डिपो का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान डिपो परिसर में खाने-पीने की अव्यवस्था और खराब गुणवत्ता को देखकर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई।

देशभर से 880 निशानेबाज पहुंचे भोपाल

69वीं नेशनल स्कूल राइफल शूटिंग प्रतियोगिता शुरू, आज से होंगे इवेंट

भोपाल। राजधानी एक बार फिर राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने जा रही है। सोमवार से भोपाल में 69वीं नेशनल लेवल स्कूल राइफल शूटिंग प्रतियोगिता 2025-26 का आयोजन शुरू हुआ है। स्पर्धा में देशभर से सैकड़ों उभरते निशानेबाज अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन सोमवार दोपहर शिवाजी नगर स्थित शासकीय सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में किया गया। उद्घाटन समारोह में मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। भोपाल महापौर मालती राय भी विशेष रूप से उपस्थित रहीं। इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों से आए 880 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। कोच, तकनीकी स्टाफ और अधिकारियों को मिलाकर कुल 1050 से अधिक लोग इस आयोजन से जुड़े हैं। इस साल प्रतियोगिता के सफल आयोजन की जिम्मेदारी मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपी गई है। मंगलवार सुबह से प्रतियोगिता के मुख्य इवेंट शुरू किए जाएंगे।

5 से 9 जनवरी तक चलेगी राष्ट्रीय प्रतियोगिता

69वीं नेशनल लेवल स्कूल राइफल शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन 5 से 9 जनवरी 2026 तक किया जा रहा है। पांच दिन चलने वाली इस प्रतियोगिता में अंडर-14 और अंडर-19 आयु वर्ग के बालक एवं बालिका वर्ग के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता में राइफल और पिस्टल दोनों स्पर्धाओं के मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। प्रतियोगिता को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए भोपाल में तीन प्रमुख स्थलों को प्रतियोगिता केंद्र बनाया गया है।

तीन अलग-अलग स्थलों पर होंगे मुकाबले

- एमपी स्टेट शूटिंग अकादमी, बिशनखेड़ी में अंडर-14 और अंडर-19 बालक एवं बालिका वर्ग की पीप और पिस्टल स्पर्धाएं आयोजित होंगी।
- बाल भवन स्कूल, श्यामला हिल्स में अंडर-14 और अंडर-19 बालक वर्ग की ओपन साइट शूटिंग प्रतियोगिता कराई जाएंगी।
- सरस्वती विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी रेसीडेंशियल स्कूल, शारदा विहार, केरवा डैम रोड पर अंडर-14 और अंडर-19 बालिका वर्ग की ओपन साइट स्पर्धाएं होंगी।

खिलाड़ियों की सुविधा के लिए कंट्रोल रूम

प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों और अधिकारियों की सुविधा के लिए सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम इंचार्ज की जिम्मेदारी जितेंद्र सोमकुंवर, डीएस धुर्वे, बबीता तोमर और प्रतिमा तिवारी को सौंपी गई है। वहीं खिलाड़ियों और स्टाफ के ठहरने की व्यवस्था के लिए रेसीडेंशियल इंचार्ज के रूप में सुरेश खंडेकर, वृंदावन वैष्णव, मंसूर अली अंसारी और अरुण विजयवर्गीय को जिम्मेदारी दी गई है।

मेडिकल और ट्रांसपोर्टेशन की भी पुख्ता व्यवस्था

प्रतियोगिता के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मेडिकल टीम की तैनाती की गई है। मेडिकल इंचार्ज की भूमिका देवेंद्र चंद्रोल, भगवान सिंह चौहान और प्रदीप राजावत निभा रहे हैं। इसके साथ ही खिलाड़ियों और अधिकारियों की आवाजाही के लिए परिवहन व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है।

एमबीबीएस छात्र ने 5वीं मंजिल से कूदकर किया सुसाइड

भोपाल। कोलार इलाके में स्थित प्रीमियम टावर कॉलोनी में एमबीबीएस छात्र ने पांचवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि छात्र पिछले तीन महीनों से अपनी महिला मित्र द्वारा अनदेखा किए जाने से मानसिक तनाव में था।

शनिवार सुबह फ्लैट की बालकनी से कूदने के बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां रविवार शाम इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। टीआई संजय सोनी के अनुसार, मृतक 21 वर्षीय सचिन सिंह एलएन मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस थर्ड ईयर का छात्र था और प्रीमियम टावर फेस-1 की पांचवीं मंजिल पर किराए के फ्लैट में रहता था। फ्लैट में उसके साथ तीन अन्य छात्र भी रहते थे।

बातचीत बंद होने से डिप्रेशन में था- पुलिस जांच में पता चला है कि कॉलेज में साथ पढ़ने वाली एक छात्रा से सचिन की नजदीकी थी, लेकिन बीते तीन महीनों से छात्रा ने उससे बातचीत बंद कर दी थी। इसी बात को लेकर वह लगातार परेशान और डिप्रेशन में था।

सचिन सिंह, मृतक

छात्रा ने उसके दोस्तों को दी थी जानकारी

शुक्रवार-शनिवार की दरम्यानी रात सचिन महिला मित्र से मिलने गया था। वहां उसने आत्महत्या की बात कही थी। इसके बाद वह फ्लैट लौट आया। छात्रा ने इस बातचीत के बाद सचिन के दोस्तों को फोन कर उसकी मानसिक स्थिति को लेकर सतर्क रहने को कहा था।

पुलिस को नहीं मिला सुसाइड नोट

हालांकि फ्लैट लौटने के बाद सचिन सामान्य व्यवहार करता दिखा और रात में सो गया। सुबह उसने बालकनी से छलांग लगा दी। पुलिस के मुताबिक, मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है।

पार्षद बृजुला सचान के जाति प्रमाण पत्र को लेकर उठे सवाल

एसडीएम ने नोटिस जारी कर पक्ष रखने को कहा

भोपाल। प्रदेश की राजधानी भोपाल के वार्ड क्रमांक 31 से भाजपा की पार्षद बृजुला सचान का जाति प्रमाण को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। शिकायत पर एसडीएम ने नोटिस जारी कर भाजपा पार्षद को अपना पक्ष रखने को कहा गया है। टीटी नगर की एसडीएम ने पार्षद को नोटिस जारी कर 23 जनवरी को कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में एकतरफा कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में कोलार निवासी शैलेष सेन ने शिकायत दी थी, जिन्होंने वार्ड-31 से पार्षद पद का चुनाव भी लड़ा था। शैलेश सेन ने आरोप लगाया है कि बृजुला सचान का जाति प्रमाण पत्र पर सवाल उठाए और उसकी जांच करने की मांग की है।

'ऊर्जस्विता सम्मान' से सम्मानित होंगी 25 महिलाएं

7 जनवरी को भोपाल में होगा भव्य सम्मान समारोह

भोपाल। हर साल की तरह अनुनय एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी द्वारा इस वर्ष भी 'ऊर्जस्विता सम्मान समारोह' का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं को उनके योगदान और उपलब्धियों के लिए सम्मान प्रदान किया जाता है। इस सम्मान समारोह में शिक्षा, प्रशासन, समाज सेवा, स्वास्थ्य, मीडिया, राजनीति, संस्कृति, खेल और उद्यमिता जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 25 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। यह समारोह बुधवार, 7 जनवरी 2026 को दोपहर 3 बजे भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान (आईएचएम), भोपाल के सभागार में आयोजित होगा। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया अध्यक्षता करेंगी, जबकि पर्यटन एवं संस्कृति राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेंद्र सिंह लोधी मुख्य अतिथि होंगे। भोपाल की महापौर मालती राय, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी परांजपे और आईएचएम के प्राचार्य डॉ. रोहित सरीन विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर मध्यप्रदेश की सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जयश्री कियावत को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अनुनय एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी की अध्यक्ष माही भजनी ने बताया कि पिछले चार वर्षों से आयोजित हो रहे ऊर्जस्विता सम्मान को समाज में व्यापक सराहना मिल रही है। इस वर्ष भी बड़ी संख्या में नामांकन प्राप्त हुए, जिनमें से ज्यूरी द्वारा 25 महिला विभूतियों का चयन किया गया। संस्था के सचिव एवं सेवानिवृत्त आईएफएस अधिकारी डॉ. ए.के. भट्टाचार्य ने बताया कि ऊर्जस्विता सम्मान का उद्देश्य समाज को सकारात्मक दिशा देने वाली प्रेरणादायक महिलाओं को मंच देना है। उन्होंने बताया कि अनुनय संस्था पिछले 15 वर्षों से गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा और विकास के लिए कार्य कर रही है।

पीड़िता ने बच्ची को जन्म दिया तब वारदात का खुलासा हुआ

भोपाल में ई-रिक्शा चालक ने नाबालिग से रेप किया

भोपाल। मिसरोद इलाके में ई-रिक्शा चालक ने एक नाबालिग के साथ रेप कर दिया। आठ महीने पहले किशोरी को अगवा कर वारदात को अंजाम दिया गया था। अब पीड़िता ने बच्ची को जन्म दिया तो मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने मामले में अज्ञात आरोपी के खिलाफ रेप का केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक 17 वर्षीय किशोरी गंजबासौदा में अपने नाना-नानी के साथ रहती है। उसके माता-पिता रायसेन जिले में रहते हैं। 1 मार्च 2025 को वह भोपाल ट्रेन से आई थी और रायसेन जाने के लिए वह ई-रिक्शा में सवार हुई थी। इस दौरान ई-रिक्शा चालक ने उसे बेहोश कर दिया और सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ रेप किया।

आरोपी की नहीं हो सकी पहचान- अभी कुछ दिन पहले पीड़िता ने एक बच्ची को अस्पताल में जन्म दिया तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया। अभी तक आरोपी की पहचान नहीं हो सकी है, इसलिए पुलिस अब पीड़िता की काउंसिलिंग करा रही है।

महिला नर्स से भी रेप- इधर, गौतम नगर इलाके में भी महिला नर्स से रेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में भी रेप का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि चौकसे नगर में रहने वाली 25 वर्षीय युवती एक निजी अस्पताल में नर्स है। जबकि आरोपी रजनीश शर्मा भी उसकी अस्पताल में मेल नर्स है। 1 जनवरी 2021 से दोनों एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में साथ रह रहे थे।

बैंकों में 5 डे वीक वर्किंग की मांग...भोपाल में धरना

एमपी नगर में इकट्ठा हुए, बोले- मांग पूरी नहीं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे

भोपाल। पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह यानी, 5 डे वीक वर्किंग की मांग को लेकर सोमवार को भोपाल में बैंककर्मियों ने धरना दिया। वे एमपी नगर में इकट्ठा हुए। यहीं पर सभा भी हुई। इससे पहले दो बार वे नारेबाजी कर चुके हैं। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि यदि केंद्र सरकार जल्द मांग को नहीं मानती है तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल भी जा सकते हैं।

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस मध्यप्रदेश के को-ऑर्डिनेटर वीके शर्मा ने बताया कि यूनियंस के आह्वान पर देशभर के बैंक अधिकारी- कर्मचारी आंदोलनरत हैं। इसके चलते सोमवार सुबह 11 से दोपहर 2.30 बजे तक पंजाब नेशनल बैंक इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स शाखा एमपी नगर के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। इसमें सभी सरकारी बैंक के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए।

देशभर में 10 लाख बैंककर्मी

यूनियंस के पदाधिकारी शर्मा ने बताया, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने बैंक की शाखा और कार्यालयों में कार्यरत बैंकिंग उद्योग के 10 लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारियों पर बढ़ते तनाव और दबाव के कारण पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह शुरू करने की मांग की थी।

वर्ष 2015 में बैंक कर्मचारी और अधिकारियों के साथ हुए द्विपक्षीय समझौते में यह तय हुआ था कि हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी होगी और इसके बदले बाकी शनिवार, जिनमें की आधा दिन बैंकों का कामकाज होता था, में पूरे दिन का कामकाज होगा।

इसके बाद हुए द्विपक्षीय समझौता के दौरान हमने बाकी शनिवार को भी छुट्टी घोषित करने की अपनी मांग को आगे बढ़ाया, लेकिन कोविड महामारी के दौरान हुए समझौता के कारण हमारी मांग को उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया। इसके बाद गत समझौता के दौरान पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह के मुद्दे को फिर से उठाया गया। इस दौरान हुई द्विपक्षीय वार्ताओं के दौरान दिसंबर 2023 को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस और बैंक प्रबंधन के बीच इस मुद्दे पर सहमति हो गई।

इस सहमति को अपनी सिफारिश के साथ बैंक प्रबंधन ने वित्त मंत्रालय केंद्र सरकार को पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू करने बाबत सिफारिश प्रेषित कर दी। कार्य के घंटे में जरूरी बदलाव, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से जरूरी मंजूरी के बाद यह लागू की जा सकेगी। इस मुद्दे को मंजूरी के लिए सरकार को सिफारिश किए हुए दो वर्ष हो गए, लेकिन सरकार ने अभी तक सहमति प्रदान नहीं की है।

पहले आश्वासन के बाद स्थगित हो गई थी हड़ताल

पदाधिकारियों ने बताया, इस मुद्दे पर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 24 और 25 मार्च 2025 को हड़ताल का आह्वान भी किया था, लेकिन हड़ताल के तीन दिन पूर्व वित्त मंत्रालय और बैंक प्रबंधन के आश्वासन के कारण हड़ताल स्थगित कर दी गई थी। इस मुद्दे में जानबूझकर की जा रही देरी के खिलाफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने फिर से आंदोलन करने का निर्णय लिया है। आने वाले दिनों में बैंककर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं।

भोपाल में अनोखे अंदाज में क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू

संस्कृत में क्रिकेट की कॉमेंट्री धोती-कुर्ता पहने खिलाड़ी

भोपाल। शिवाजी नगर स्थित अंकुर खेल मैदान पर सोमवार से वैदिक ब्राह्मणों का क्रिकेट मैच शुरू हो गया है। खिलाड़ी जर्सी नहीं, बल्कि धोती-कुर्ता पहनकर मैदान में उतरे हैं। हिंदी या अंग्रेजी की बजाय संस्कृत भाषा में क्रिकेट कमेंट्री की जा रही है। यह आयोजन महर्षि मैत्री मैच शृंखला-6 के तहत 5 से 9 जनवरी तक चलेगा। संस्कृत का प्रचार-प्रसार और विस्तार कैसे हो यह भी टूर्नामेंट में बताया जा रहा है। प्रतियोगिता के विजेता-उप विजेता टीमों को पुरस्कार दिए जाएंगे। मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार के रूप में श्रीमद भागवत गीता और श्रीरामचरित मानस भेंट की जाएगी। विजेता टीम को बागेश्वरधाम के पीठाधीश्वर पं. धीरेंद्र

वैदिक ब्राह्मण युवा खेल कल्याण समिति यह आयोजन परशुराम कल्याण बोर्ड के संयोजन से कर रही है।

दोपहर 2 बजे खेल मंत्री विश्वास सारंग ने टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। इसके बाद टीमें मैदान में दो-दो हाथ हाजमाने के लिए उतर गईं। बोर्ड के अध्यक्ष विष्णु राजोरिया ने बताया, टूर्नामेंट में पूरे प्रदेश से 24 टीमें हिस्सा ले रही हैं। यह आयोजन लगातार छठे वर्ष किया जा रहा है। मैच दौरान क्रिकेट से जुड़े रोजमर्रा के शब्द भी संस्कृत में बोले जाएंगे।

पं. धीरेंद्र शास्त्री से मिलेंगे विजेता- समिति के कोषाध्यक्ष अवनीश त्रिवेदी ने बताया कि टूर्नामेंट में दिल्ली, महाराष्ट्र से भी टीमें आई हैं। शास्त्री से मिलने का मौका मिलेगा।

ऐसे आयोजन काशी में हुए- मैच के दौरान खिलाड़ी धोती-कुर्ता के साथ मस्तक पर त्रिपुंड और तिलक लगाए नजर आ रहे हैं। पिच पर रन लेने से लेकर आउट होने तक हर संवाद संस्कृत भाषा में होगा। यह इसे प्रदेश का अनूठा टूर्नामेंट बनाती है। इससे पहले इस तरह का आयोजन काशी में ही देखने को मिलता रहा है। महर्षि मैत्री समिति का उद्देश्य खेल से भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा को जन-जन तक पहुंचाना है। भगवान श्रीकृष्ण भी कन्दुक क्रीड़ा यानी गेंद का खेल खेलते थे। पिछले साल भी अंकुर खेल मैदान पर ही यह आयोजन हुआ था।

प्रदेश के विशेषज्ञ ट्रांसको इंजीनियर्स ने रिकॉर्ड समय में 50 एमवीए पॉवर ट्रांसफार्मर को किया ऊर्जीकृत

भोपाल। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एम.पी. ट्रांसको) ने मालनपुर (भिंड) में तकनीकी दक्षता, सटीक योजना और उत्कृष्ट समन्वय का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए लगभग 15 दिन में 50 एमवीए क्षमता के नये पावर ट्रांसफार्मर का ट्रांसपोर्ट, स्थापना, संपूर्ण तकनीकी परीक्षण एवं ऊर्जीकरण कर एक बेहद अनुकरणीय कार्य किया है।

सामान्य परिस्थितियों में किसी भी पावर ट्रांसफार्मर के साइट पर पहुँचने के बाद उसके इरेक्शन, टेस्टिंग, आयल फिल्टेरेशन एवं ऊर्जीकरण में एक माह या उससे अधिक समय लग जाता है, किंतु मालनपुर के ओद्योगिक क्षेत्र मे विद्युत की सामान्य बहाली की प्राथमिकता के कारण एम पी ट्रांसको ने तकनीकी रूप से जटिल,

जोखिमपूर्ण और चुनौतीपूर्ण कार्य को मुख्य अभियंता (परीक्षण एवं संचार) श्री अमर कीर्ति सक्सेना के कुशल निर्देशन में दिन रात एक कर न्यूनतम संभव समय में सफलतापूर्वक पूरा किया।

एम.पी. ट्रांसको के इतिहास में यह विरला अवसर है जब पुराने फेल ट्रांसफार्मर को हटाकर, नए उच्च क्षमता के पावर ट्रांसफार्मर का सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन , स्थापना, आवश्यक सभी तकनीकी परीक्षण एवं ऊर्जीकरण का बेहद संवेदनशील कार्य लगभग 15 दिनों में संभव हो सका हो।

ऊर्जा मंत्री ने दी बधाई- मालनपुर सबस्टेशन में रिकॉर्ड समय में नये पावर ट्रांसफार्मर के ऊर्जीकृत होने पर बधाई देते हुए मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा कि एम.पी. ट्रांसको की यह सफलता उसके तकनीकी क्षमता, सुनियोजित रणनीति और टीमवर्क का सशक्त प्रमाण है, जो यह दर्शाती है कि प्रतिबद्धता और विशेषज्ञता से असंभव प्रतीत होने वाले कार्य भी संभव बनाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि के परिणामस्वरूप अब मालनपुर में लक्ष्मणपुरा औद्योगिक क्षेत्र के इंडस्ट्रियल फीडरों को पुनः सामान्य, निर्बाध एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति संभव हो सकेगी।

न्यूनतम समय में पूर्ण हुआ अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य : एमडी श्री तिवारी

एम.पी. ट्रांसको के प्रबंध संचालक सुनील तिवारी ने बताया कि एम.पी. ट्रांसको के 220 केवी सबस्टेशन मालनपुर में तकनीकी कारणों से 19 दिसंबर को फेल हुए 40 एमवीए क्षमता के पावर ट्रांसफार्मर के स्थान पर नए 50 एमवीए क्षमता के पावर ट्रांसफार्मर को न्यूनतम संभव समय में ट्रांसपोर्ट कर सबस्टेशन में स्थापित एवं ऊर्जीकृत किया गया। उन्होंने बताया कि पावर ट्रांसफार्मर की डिस्मेंटलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, साइट प्रिपरेशन, इरेक्शन, ऑयल फिल्ट्रेशन, कमिशनिंग एवं टेस्टिंग की संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत तकनीकी, समय-साध्य एवं सुरक्षा-संवेदनशील होती है।

मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र के उपभोक्ताओं को हो रही असुविधा को ध्यान में रखते हुए, एम.पी. ट्रांसको के प्रदेश के विभिन्न भागों से नियुक्त किये गए अनुभवी अधीक्षण अभियंताओं ने स्थानीय तकनीकी टीमों के साथ निरंतर 15 दिनों तक 24x7 कार्य करते हुए उच्च तकनीकी दक्षता, सतर्कता एवं समन्वय के साथ इस चुनौती को सफलतापूर्वक पूरा किया।

संपादकीय

यह अमेरिका की दादागिरी है...

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर वहां की डेल्टा फोर्स ने जिस तरह वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को रातों रात उनके घर से उठा लिया और अब न्यूयॉर्क में जेल में रखा है, उसने सारी दुनिया को हैरत और चिंता में डाल दिया है। अमेरिका में उन पर ड्रग तस्करी को लेकर मुकदमा चलाया जाएगा। लेकिन जो हुआ, वह तो शुद्ध रूप से अंतरराष्ट्रीय दादागिरी है, जिसमें किसी भी देश की संप्रभुता का कोई अर्थ नहीं है। इस घटना से उन तमाम देशों में घबराहट है, जो अमेरिका विरोधी हैं या उसके पिछलग्गू नहीं हैं। ट्रंप का संदेश साफ है कि जो अमेरिकी का गुलाम नहीं बनेगा, वह जी नहीं सकता। हालांकि अमेरिकी सेना की इस कार्रवाई से वेनेजुएलावासियों में गहरा आक्रोश है। वहां की सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज़ को अंतरिम राष्ट्रपति का पदभार को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रोड्रिग्ज़ को यह ज़िम्मेदारी सौंपना 'प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने और देश की रक्षा सुनिश्चित करने' के लिए ज़रूरी है। इस बीच भारत ने इस घटनाक्रम पर गहरी चिंता जताई है, लेकिन इसकी निंदा नहीं की है। भारत सरकार ने भारतीयों से कहा कि वो फिलहाल वेनेजुएला की यात्रा से बचें। जाहिर है कि भारत भी अमेरिका के साथ अपने रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहता। यह तो माना ही जा रहा था कि जिस तरह अमेरिका ने वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति मादुरो पर शिकंजा कस दिया था, उसका अंजाम यही होना था। हालांकि यह इतनी आसानी और बिना किसी खास विरोध के हो जाएगा, यह नहीं सोचा था। इस घटनाक्रम से यह भी साफ हुआ कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए ने राष्ट्रपति के अंगरक्षकों तक अपनी घुसपैठ कर ली थी और वो सीआईए के हाथों बिक गए थे। यह खुलासा भी चौंकाने वाला है कि मादुरो की सुरक्षा में ज्यादा सुरक्षाकर्मी पड़ोसी देश क्यूबा के थे। इससे यह भी पता चलता है कि मादुरो भले ही अमेरिका को चुनौती देने की कितनी ही डींगे हांक रहे हों, लेकिन उनका घर कितना कमजोर था। अमेरिका मादुरो पर ड्रग तस्करी में शामिल होने का आरोप लगाता रहा है। इसी बुनियाद पर वह उन्हें हटाना चाहता था। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क के मेयर और ट्रंप विरोधी जोहरान ममदानी ने मादुरो की इस तरह गिरफ्तारी को 'युद्ध की कार्रवाई' और 'संघीय और अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों का उल्लंघन' बताया है। उधर ट्रंप ने कहा कि जब तक वेनेजुएला में कोई ठीक सरकार नहीं बनती, तब तक अमेरिका ही वेनेजुएला को चलाएगा। अब यह पूरी तरफ साफ हो चुका है अमेरिका अपने आसपास के देशों में अपना दबदबा कायम रखना चाहता है। कोई उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखे, यह अमेरिका को मंजूर नहीं है। दूसरे, वेनेजुएला में जिस कुशलता से तख्ता पलट हुआ है, वह वेनेजुएला के हमदर्द रूस और चीन के लिए भी कड़ी चेतावनी है, क्योंकि ये दोनों देश मादुरो को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सके। इस घटना के बाद चीन भी ताइवान पर हमले के बारे में दस बार सोचेगा। ट्रंप ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि उनकी लड़ाई अब दुनिया भर में खनिज संसाधनों पर कब्जे को लेकर है। अमेरिका वेनेजुएला के तेल भंडारों पर कब्जा चाहता है। इसी तरह उसकी नजर ताइवान के लीथियम भंडार और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खनिज भंडारों पर भी है। भविष्य में अमेरिका की इस लालची वृत्ति के खिलाफ दुनिया भर में देशों की नए सिरे से गोलबंदी होगी। यह 2026 में तीसरे विश्वयुद्ध की आहट है। वेनेजुएला के बाद अगला नंबर उसके दोस्त क्यूबा, कोलंबिया, पनामा का भी हो सकता है। लेकिन अमेरिका जो कर रहा है, वह अंतरराष्ट्रीय नैतिकता के खिलाफ है। इसका विरोध होना चाहिए।

राम रहीम को पैरोल बनाम न्याय प्रक्रिया में देरी

2017 में सजा मिलने के बाद अब तक यह सबसे निरंतर और लंबा पैरोल सिलसिला है, जिसने न केवल न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं बल्कि पीड़ित परिवारों और समाज में नाराजगी भी पैदा की है। गुरमीत राम रहीम ने सोमवार को जेल से बाहर आते ही अपने समर्थकों के स्वागत में पहुंची बड़ी संख्या में गाड़ियों के काफिले के बीच सिरसा डेरा सच्चा सौदा के लिए प्रस्थान किया। पैरोल अवधि के दौरान वह वहीं रहेंगे। रिकॉर्ड्स के अनुसार, 2017 से अब तक वह कुल 405 दिन से अधिक समय जेल से बाहर रह चुके हैं। यानी सिर्फ 8 साल और 4 महीने की सज़ा में उन्होंने लगभग एक पूरा साल जेल की सुरक्षा से बाहर गुज़ारा है।

नजरिया

अजय कुमार

लेखक लखनऊ निवासी वरिष्ठ पत्रकार हैं।

हरियाणा के रोहतक स्थित सुनारिया जेल में बलात्कार और हत्या के गंभीर आरोपों में 20 साल की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को 15वीं बार पैरोल मंजूर कर दी गई है। इसके तहत वह करीब 40 दिनों के लिए जेल से बाहर सिरसा डेरा में रहेंगे। 2017 में सजा मिलने के बाद अब तक यह सबसे निरंतर और लंबा पैरोल सिलसिला है, जिसने न केवल न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं बल्कि पीड़ित परिवारों और समाज में नाराजगी भी पैदा की है।गुरमीत राम रहीम ने सोमवार को जेल से बाहर आते ही अपने समर्थकों के स्वागत में पहुंची बड़ी संख्या में गाड़ियों के काफिले के बीच सिरसा डेरा सच्चा सौदा के लिए प्रस्थान किया। पैरोल अवधि के दौरान वह वहीं रहेंगे। रिकॉर्ड्स के अनुसार, 2017 से अब तक वह कुल 405 दिन से अधिक समय जेल से बाहर रह चुके हैं। यानी सिर्फ 8 साल और 4 महीने की सज़ा में उन्होंने लगभग एक पूरा साल जेल की सुरक्षा से बाहर गुज़ारा है।पहली बार उन्हें 24 अक्टूबर 2021 को बीमार मां से मिलने के लिए सिर्फ एक दिन की पैरोल दी गई थी। इसके बाद 21 मई 2021 को भी मां की बीमारी के कारण एक दिन की पैरोल मिली। लेकिन तीसरी बार, 7 फरवरी 2022, उन्हें 21 दिन के लिए जेल से बाहर आने की अनुमति मिली, उस समय पंजाब में विधानसभा चुनाव चल रहे थे। चौथी बार 17 जून 2022, उन्हें 30 दिन के लिए पैरोल मिली, हरियाणा में निकाय चुनाव के दौरान। पांचवीं बार 15 अक्टूबर 2022 को उन्हें 40 दिन के लिए जेल से बाहर रहने की अनुमति मिली, उसी दौरान आदमपुर उपचुनाव था।

इसके बाद भी सिलसिला लगातार चलता रहा। छठी बार 21 जनवरी 2023 को शाह सतनाम जयंती के मौके पर 40 दिन, सातवीं बार 20 जुलाई 2023 को जन्मदिन के समय 30 दिन, आठवीं बार 21 नवंबर 2023 को राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान 21 दिन, नौवीं बार 19 जनवरी 2024 को लोकसभा चुनाव के समय 50 दिन, दसवीं बार 13 अगस्त 2024 को जन्मदिन के आसपास 21 दिन, ग्यारहवीं बार 1 अक्टूबर 2024 हरियाणा चुनाव में 21 दिन, बारहवीं बार 28 जनवरी 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय 30 दिन, तेरहवीं बार 9 अप्रैल 2025 डेरा सच्चा सौदा स्थापना दिवस के मौके पर 41 दिन, चौदहवीं बार 5 अगस्त 2025 जन्मदिन के आसपास 40 दिन और अब पंद्रहवीं बार 3 जनवरी 2026 को 40 दिन के लिए पैरोल मिली।

इस लगातार पैरोल सिलसिले को देखकर यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या बलात्कार और हत्या जैसे गंभीर अपराध में सज़ायाफ्ता के प्रति प्रशासन और सरकार की नरमी का कारण राजनीतिक दबाव या सामाजिक स्थिति है। पैरोल नियमों के अनुसार कैदी को केवल परिवार में मौत, गंभीर बीमारी, करीबी की शादी या किसी अन्य अत्यावश्यक मानवीय कारण से ही अस्थायी रूप से जेल से बाहर आने की अनुमति मिल सकती है। लेकिन गुरमीत राम रहीम को जन्मदिन, चुनाव या धार्मिक आयोजन जैसे अवसरों पर बार-बार जेल से बाहर भेजा जाना नियमों की सीमाओं के परे है।

सामाजिक संगठनों और पीड़ित परिवारों ने इस बार-बार की पैरोल की अनुमति को न्यायिक मर्यादाओं के विरुद्ध बताया है। ज्ञानी राम सिंह खासला ने इसे जख्मों पर नमक छिड़कने के समान बताया। उनका कहना है कि सरकार लंबे समय से जेलों में बंद सिख कैदियों की रिहाई के मुद्दे पर चुप है, लेकिन बलात्कारी गुरमीत राम रहीम को लगातार पैरोल मिल रही है, जिससे समाज और समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। इस सिलसिले में आँकड़े भी हैरान कर देने वाले हैं। आठ साल और चार महीने की सज़ा में गुरमीत राम रहीम कुल 387 दिन जेल से बाहर रह चुके हैं। यानी वह इस सज़ा का एक वर्ष से अधिक समय जेल की दीवारों से दूर गुज़ार चुके हैं। वहीं, आसाराम बापू को जेल से बाहर आने में एक दशक से अधिक समय लग गया और उन्हें हाल ही में मेडिकल ग्राउंड पर छह महीने की अंतरिम जमानत मिली। कुलदीप सेंगर को बलात्कार के लिए उम्रकैद मिली थी, जिसे हाईकोर्ट ने सस्पेंड किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पलट दिया। इस तुलना से यह स्पष्ट होता है कि गुरमीत राम रहीम को दी जाने वाली रियायत असाधारण और विवादास्पद है। सामाजिक और राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं कि पैरोल का बार-बार मिलना केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसमें राजनीतिक और सामाजिक कारणों का असर भी देखा जा सकता है। चुनाव के समय, जन्मदिन या धार्मिक आयोजन के मौके पर पैरोल देना न्याय व्यवस्था की पारदर्शिता और समानता पर सवाल खड़ा करता है।

पारिवारिक और मानवीय कारणों से पैरोल दी जाती है, लेकिन राजनीतिक अवसरों और व्यक्तिगत उत्सवों के लिए बार-बार पैरोल देना न्याय और समाज के लिए गंभीर चुनौती है। इससे पीड़ित परिवारों की पीड़ा और बढ़ती है, और यह संदेश जाता है कि समाज में कुछ लोग कानून से अलग विशेषाधिकार पा सकते हैं।गुरमीत राम रहीम के बार-बार जेल से बाहर आने के सिलसिले ने यह भी उजागर किया कि सज़ा का वास्तविक अर्थ और जेल का उद्देश्य क्या है, इसे आम जनता और पीड़ित परिवार सही ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं। अदालत और प्रशासन के निर्णयों में समानता और पारदर्शिता होनी चाहिए, ताकि न्याय व्यवस्था में विश्वास बनाए रखा जा सके। सामाजिक दृष्टि से यह भी देखा गया है कि ऐसे अपराधियों के बार-बार जेल से बाहर आने से समुदायों की भावनाएं आहत होती हैं और समानता का संदेश कमजोर होता है। कई लोग कहते हैं कि अगर पैरोल केवल कानूनी औचित्य के आधार पर दी जाए, तो न्याय की मर्यादा और समाज में विश्वास दोनों बनाए रखा जा सकता है।इस बार-बार पैरोल मिलने के सिलसिले ने यह साबित कर दिया है कि पैरोल केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और मानवीय बहस का विषय भी बन गई है। न्यायपालिका और प्रशासन को इसे और अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और न्यायसंगत बनाना चाहिए, ताकि किसी भी अपराधी को विशेषाधिकार प्राप्त न हो और सभी पीड़ितों को न्याय मिले।

सामयिक

डॉ. मनीष जैसल

लेखक मीडिया शिक्षक हैं।

विकास की दौड़ में पीछे छूटता बचपन

दुनिया भले ही विकास की रफ़्तार पर गर्व कर रही हो, लेकिन बच्चों का पोषण आज भी मानवता की सबसे बड़ी चिंता बना हुआ है। 2023 के यूनिसेफ़ आँकड़े बताते हैं कि पाँच साल से कम उम्र के लगभग 48 लाख बच्चे हर साल दुनिया भर में जान गंवा देते हैं। इनमें से लगभग 45 प्रतिशत मौतों में कुपोषण एक प्रमुख जोखिम कारक के रूप में मौजूद रहता है।

आज़ादी के बाद के शुरुआती दशकों में यह तस्वीर और भी भयावह थी। 1970-80 के दशक तक राष्ट्रीय पोषण सर्वे बताते हैं कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में प्री-स्कूल आयु के आधे से ज़्यादा बच्चे कम वज़न और ठिगने कद के शिकार थे, कई सर्वे में यह अनुपात 55-60 प्रतिशत तक दर्ज हुआ। यह वह दौर था जब अकाल की यादें ताज़ा थीं, परिवारों का लक्ष्य सिर्फ पेट भर अनाज जुटाना था । थाली में दाल, दूध, फल-सब्ज़ियों की विविधता तो दूर की बात थी, कई घरों में एक समय का ठीक से खाना मिलना भी चुनौती था।

1990 के दशक के बाद राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे (एनएफएचएस) और 2016-18 के व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वे (सीएनएनएस) ने तस्वीर को और साफ़ किया। सीएनएनएस के अनुसार भारत में पाँच वर्ष से कम आयु के लगभग 34.7 प्रतिशत बच्चे ठिगने (स्टंटेड) और 33.4 प्रतिशत कम वज़न वाले पाए गए - यानी हर तीसरा भारतीय बच्चा विकास की उस ऊँचाई तक नहीं पहुँच पा रहा, जो उसकी उम्र के अनुसार होनी चाहिए, जबकि अर्थव्यवस्था के ग्रोथ-रेट के आँकड़े चमकते दिखते हैं।

यह संकट पूरे देश में एक जैसा नहीं है। एनएफएचएस-5 के विश्लेषण बताते हैं कि मेघालय में ठिगने बच्चों की हिस्सेदारी लगभग 46 प्रतिशत के आसपास है, बिहार में 42-43 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी यह आँकड़ा 40 प्रतिशत के करीब है। इसके विपरीत सिक्किम और पुडुचेरी जैसे राज्यों में यह दर लगभग आधी है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कई आदिवासी बहुल ज़िलों में भी स्टंटिंग और कम वज़न का बोझ राष्ट्रीय औसत से बहुत ज़्यादा है। हाल के पोषण ट्रैकर और संसद में दी गई जानकारियाँ दिखाती हैं कि कई बड़े राज्यों में आज भी 40-50 प्रतिशत तक आंगनवाड़ी में पंजीकृत बच्चे ठिगने दर्ज हो रहे हैं। उत्तराखंड जैसे अपेक्षाकृत छोटे राज्यों के कुछ ज़िलों में भी स्टंटिंग 30 प्रतिशत से ऊपर पाई गई है। यह बताता है कि कुपोषण अब सिर्फ 'गरीबी' की समस्या नहीं, बल्कि क्षेत्रीय असमानता, प्रशासनिक क्षमता और सामाजिक व्यवहार- इन सबका मिला-जुला संकट है।

कुपोषण की जड़ें सिर्फ थाली की मात्रा में नहीं, उसकी गुणवत्ता और घर-समाज की कुप्रथाओं में भी छिपी हैं। सुरक्षित पेयजल, शौचालय, सीवर और स्वच्छता की कमी बच्चों के पोषण को सीधे चोट पहुँचाती है। जहाँ गंदा पानी और खराब स्वच्छता व्यवस्था है, वहाँ दस्त, निमोनिया और बार-बार होने वाले संक्रमण बच्चों के शरीर से पोषक तत्वों को लगातार खींचते रहते हैं, और बच्चा चाहे जो भी खाए, शरीर उसे ठीक से पकड़ ही नहीं पाता। परिणाम यह होता है कि कुपोषण-बीमारी-गरीबी का दुष्चक्र टूटने के बजाय और कसता जाता है।

नीतिगत स्तर पर भी देश ने लंबा सफ़र तय किया है। आईसीडीएस के बाद 2018 में 'पोषण अभियान' शुरू हुआ, जिसका लक्ष्य 0-6 वर्ष के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं में स्टंटिंग, अंडरवेट, एनीमिया और कम जन्म-वज़न को तेज़ी से घटाना है। अब 'मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0' के तहत पोषण, स्वास्थ्य, जल-स्वच्छता, शिक्षा और कृषि जैसे 18 मंत्रालयों को एक मंच पर लाने की कोशिश हो रही है। फोर्टिफाइड अनाज, मोटे अनाज (मिलेट्स), समुदाय-आधारित उपचार मॉडल और आंगनवाड़ी नेटवर्क को मज़बूत करना इस प्रयास का हिस्सा हैं। लेकिन काग़ज़ पर बनी अच्छी योजनाएँ तभी असर दिखाती हैं, जब उनके साथ व्यवहार-परिवर्तन, जवाबदेही और स्थानीय स्तर पर नवाचार भी जुड़े हों।

इसी बीच एक नया सवाल भी सामने है, क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) इस लड़ाई की साथी बन सकती है? कई राज्यों में आंगनवाड़ी केंद्रों के पास अब स्मार्टफोन और ग्रोथ-मॉनिटरिंग उपकरण हैं। 'पोषण ट्रैकर' जैसे डिजिटल टूल बच्चों के वज़न, कद और उपस्थिति का रियल-टाइम डेटा दर्ज कर रहे हैं। इस डेटा पर एआई आधारित मॉडल काम करके यह संकेत दे सकते हैं कि किस ज़िले या बस्ती में स्टंटिंग या वेस्टिंग बढ़ने के शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं, ताकि समय रहते अतिरिक्त भोजन, स्वास्थ्य शिविर या घर-घर परामर्श की व्यवस्था की जा सके।

ज़मीनी स्तर पर एआई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की तरह एक 'डिजिटल सहकर्मी' बन सकती है, जो स्थानीय भाषा में सरल तरीके से बताए कि किस बच्चे को तुरंत डॉक्टर के पास रेफ़र करना है, किन माताओं को एनीमिया या किशोर गर्भावस्था के कारण अधिक निगरानी की ज़रूरत है, और किस घर में बार-बार दस्त या बुखार की वजह से पोषण का नुकसान हो रहा है। चेहरे की पहचान और डिजिटल उपस्थिति से यह भी देखा जा सकता है कि जो राशन काग़ज़ पर बँट रहा है, वह सच में बच्चों तक पहुँच भी रहा है या नहीं। लेकिन इसके साथ यह सच भी स्वीकार करना होगा कि जहाँ इंटरनेट नहीं, जहाँ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय ही मुश्किल से मिलता है, वहाँ तकनीक अगर बिना तैयारी के थोपी गई तो वह मददगार के बजाय बोझ बन जाएगी।

कुपोषण के खिलाफ़ जंग सिर्फ तकनीक, सिर्फ योजना या सिर्फ नारेबाज़ी से नहीं जीती जा सकती। आज़ादी के बाद हमने अकाल और व्यापक भुखमरी पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया है, लेकिन 'छिपी हुई भूख' - यानी कुपोषण अब भी हमारी सबसे बड़ी राष्ट्रीय चुनौती है।

मौत के कारणों की पड़ताल और कदम उठाना जरूरी

इंदौर का भागीरथपुरा

डॉ. चन्दर सोनाने

लेखक एमपी जनसंपर्क विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं।

देश के सबसे स्वच्छ शहर इन्दौर में गंदे और जहरीले पानी से 16 लोग मारे गए। उनके लिए पीने का पानी मौत का पानी बन गया। इन्दौर के लिए यह एक कलंक है। पीने का पानी मौत का पानी क्यों और कैसे बना ? इसके कारणों की पड़ताल करना जरूरी है और यह भी जरूरी है कि अब कभी ऐसा नहीं हो। इसके लिए ठोस और सख्त कदम उठाए जाए। मध्यप्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अस्पताल पहुंचकर भर्ती मरीजों से मिलकर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त की और इन्दौर नगर निगम के आयुक्त श्री दिलीप कुमार यादव को आयुक्त पद से हटाकर भोपाल भेज दिया है। इसके साथ ही अपर आयुक्त श्री रोहित सिसोनिया और नर्मदा प्रोजेक्ट के 13 साल से प्रभारी अधीक्षण मंत्री श्री संदीप श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया है। किन्तु इतना ही काफी नहीं है। हर स्तर पर हुई लापरवाही की पड़ताल कर हर स्तर के दोषी व्यक्तियों को भी सजा मिलनी ही चाहिए।

इंदौर के भागीरथपुरा में पीने के पानी की जब जाँच की गई तो पहली रिपोर्ट 4 दिन बाद आई। उस रिपोर्ट में अनेक खतरनाक बैक्टीरिया पाए गए, जिसने पीने के पानी को मौत का पानी बना दिया। जाँच में जो प्रमुख खतरनाक बैक्टीरिया पाए गए, वे सब मौत के प्रमुख कारण है।

दूषित पानी की जाँच में प्रमुख रूप से 6 खतरनाक बैक्टीरिया मिले, वे इस प्रकार हैं-फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, ई-कोलाई, स्यूडोमोनास एरूजिनोसा, विब्रियो स्पीशीज, क्लेबसेला स्पीशीज, सिट्रोबेक्टर स्पीशीज। इन सभी बैक्टीरियाओं ने पीने के पानी में गटर के दूषित पानी के मिलने से पानी को जहरीला बना दिया। इनसे दस्त, उल्टी, पेटदर्द, फेफड़े और खून में इन्फेक्शन, हैजा, डिहाइड्रेशन, फेफड़े, मूत्र मार्ग और पेट में संक्रमण होता है, जो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबके लिए खतरनाक होते हैं।

जहरीले पानी को पीने के कारण जहाँ 16 अकाल मौतें हो गई, वहीं 201 मरीज अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं और 32 की हालत गंभीर है। 71 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अभी तक एक हजार से अधिक मरीजों की जाँच हो चुकी है। अस्पतालों में भर्ती मरीजों का इलाज जारी है। दुख की बात तो यह है कि अभी भी दूषित पानी के लिए मुख्य रूप से दोषी नगर निगम ने जबलपुर हाईकोर्ट में गंदे पानी से सिर्फ 4 लोगों की मौत को स्वीकार किया है। इस पर हाईकोर्ट ने प्रश्न भी उठाया कि जो 16 लोग मारे गए, उनकी जान कैसे गई ? विभाग लिपापोती में लगा है। यह नहीं होना चाहिए। सच सामने आना ही चाहिए।

इन्दौर नगर निगम क्षेत्र में दूषित पानी पीने से हुई मौत की खबर प्रदेश ही नहीं राष्ट्रीय अखबारों में भी आ गई है। इन्दौर ही नहीं बल्कि प्रदेश के हर शहर में पीने के पानी में नाली का पानी मिलने की खबर मीडिया में आए दिन आती रहती है। उदाहरण के लिए उज्जैन के आदर्श नगर और महाश्वेता नगर में भी पीने के पानी में गटर का गंदा पानी मिल रहा है जिसे नागरिक पीने के लिए अभिशप्त है। अनेक जगह पाईप लाईन लिकेज होने से वह पीने के पानी के साथ मिल रहा है। अन्य शहरों में भी ऐसी स्थिति होने की संभावना है। इसलिए प्रदेश के सभी शहरों में एक विशेष अभियान चलाकर पीने के पानी की लाईनों की सघन जाँच की जानी चाहिए और जहाँ भी नाली का पानी पीने के पानी में मिल रहा है, उसे तुरंत बंद कर सुधार कार्य किया जाना चाहिए। यह नहीं होगा तो फिर किसी दिन किसी अन्य शहर से ऐसे ही मौत के पानी की खबर आयेगी। ऐसी स्थिति पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। हाल ही में एक बुरी खबर आई है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी में प्रकाशित एक रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है कि हमारे देश का लगभग 70 प्रतिशत पीने का पानी दूषित है। पानी की गुणवत्ता में भारत 122 देशों में 120वें पायदान पर है। यानी नीचे से तीसरे नम्बर पर हमारी स्थिति है। यही नहीं रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि भारत में 60 करोड़ लोग अत्यधिक जल संकट का सामना कर रहे हैं। हर साल करीब 2 लाख लोगों की मौत गंदे पानी के कारण होती है। उक्त रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2030 तक देश में पानी की माँग उपलब्ध आपूर्ति से दोगुनी होने की संभावना है। इससे करोड़ों लोगों के सामने और ज्यादा बड़ा संकट खड़ा होने वाला है ! उक्त रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सन 2005 से 2022 के बीच भारत में जलजनित बीमारियों के 20.98 करोड़ से अधिक मामले दर्ज किए गए है। ये वे मामले हैं जो दर्ज हुए हैं। इससे कई अधिक मामले ऐसे हैं जो दर्ज ही नहीं होने पाए। दूषित पानी के कारण फैलने वाली बीमारियों में डायरिया, हैजा, टाइफाइड और वायरल हेपेटाइटिस शामिल है। सर्वाधिक 86 प्रतिशत केस डायरिया के पाए गए हैं। टाइफाइड दूसरे नम्बर पर रहा। पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश और उत्तरप्रदेश में हुई मौतों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है। यह अत्यन्त गंभीर मामला है। उक्त कठिन परिस्थिति में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को चाहिए कि वे पीने के पानी में गंदा पानी नहीं मिल पाए, इसके लिए प्राथमिकता के आधार पर विशेष अभियान चलाया जाए। अभियान के दौरान जहा भी जरूरी हो, वहाँ तुरंत सुधार कार्य किया जाना आवश्यक है। यह नहीं होगा तो फिर इन्दौर जैसा प्रकरण देश के अन्य शहरों में भी होने की पूरी संभावना है। यह बहुत बड़ा संकट है। इसे दूर करना केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी है।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

जवाहर चौधरी

लेखक व्यंग्यकार हैं।

हुक्काम लुटेरा, बोल यारी के

राजनीति की दुनिया में बड़े-बड़े रहस्य छुपे हुए हैं। हम में से बहुत से लोग नहीं जानते कि अंग्रेज बड़े दुष्ट थे। व्यापारी बनकर आए थे और हुकूमत करने लगे। जब सत्ता उनके हाथ में आ गई तो उन्होंने लूट का नाम बदल कर व्यापार कर दिया। भारत का वैभव उन्हें सोने की खदान के समान दिखा तो लंबे समय तक खुदाई का इरादा हो गया। देश में मतभेदों की, ऊँच- नीच की, जाति- धर्म की नफरत की फसल लहलहा रही थी। उन्होंने लोगों में पल रही नफरत को और बड़ा किया। एक धरम के लोग दूसरे से दुश्मनी पालने लगे। लोगों को बताया गया कि उनका धरम खतरे में है। सभी धर्म वालों को उन्होंने गुपचुप मदद की। कान में फुसफुसा कर हर एक को दूसरे से अच्छा और श्रेष्ठ कहा। धरम के लोग मूर्ख बनते रहे। यही नीति जातियों को लेकर भी रही। पूरा समाज बँटते बँटते उनके सामने भेड़ बकरी की तरह हो गया। उन्होंने पुलिस बनाई, लेकिन जनता को डराने के लिए। अंग्रेज अपनी मर्जी से इस विशाल देश को हाँकने लगे। अंग्रेज बड़े चालाक थे। अंग्रेज जानते थे कि जब पेट खाली हो तो जनता को भव्य आयोजनों और भविष्य के सपनों में उलझा देना चाहिए ।

राजनीति में समाज को सिर्फ बांटने लड़ाने से ही काम नहीं चलता है। कलाई खुल जाने का डर भी होता है । कुछ अच्छे काम भी इसलिए करना होते हैं कि लगे सरकार विकास करना चाहती है। अंग्रेज भेड़िये थे लेकिन उन्होंने बहुत से अच्छे काम भी किये, या यह कहना ठीक होगा कि करना पड़े। सड़के नहीं थी तो सड़के बनवाई। रेलवे शुरू की, डाक व्यवस्था बनाई, स्कूल बनाए, अस्पताल भी बनाए। कुछ अच्छे कामों का परिणाम यह हुआ कि एक दूसरे से नफरत करने वाला समाज अंग्रेजों को महान मानने लगा। लेकिन बहुत से लोग अंग्रेजों की इस चालाकी को समझ रहे थे। वे जब भी मौका मिलता सरकार की आलोचना करते और बताते कि अंग्रेज बगुला भगत हैं। अंग्रेजों ने आलोचना को राजद्रोह घोषित किया और कइयों को लाठी से पिटवा कर मरवा दिया। सरकार के खिलाफ बोलने वालों को जेल में डाल देना आम बात थी। अंग्रेज बड़े लोमड़ थे। उन्होंने देखा कि दलित और आदिवासियों की बड़ी संख्या है। वे शासन की जरूरत में काम आ सकते थे तो उनके लिए चर्च के दरवाजे, स्कूल के दरवाजे, और सेना के दरवाजे खोल दिये। महिलाओं के लिए भी उन्होंने कुछ काम किये। अंग्रेज बड़े चालू थे। उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया, उन्हें शिक्षित करने का प्रयास किया। अब अंग्रेज महिलाओं दलितों और पिछड़ों के हितैषी हो गए। लेकिन अंदर ही अंदर लोग मानते थे कि अंग्रेज बड़े कमीने हैं। अंग्रेज भी जानते थे कि लोग उन्हें कमीना मानते हैं। लेकिन कुछ वर्षों की सत्ता में वे बड़े ढीठ हो गए थे। शासन करने वालों को आमतौर पर लज्जा नहीं आती है। अंग्रेज अपनी दाढ़ी मूंछ और परिधान पर बहुत ध्यान देते थे। वे बड़ी-बड़ी कोठियों में रहते थे लेकिन उनकी अपनी निजी कोठी नहीं होती थी। वे लूट का माल विदेशों में जमा करके रखते थे ।

देश में बहुत से राजा नवाब तब भी थे। उन्हें हैंगर की तरह अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया। जैसे हैंगर में कपड़े टांगे जाते हैं वैसे ही उन पर बहुत कुछ लाद रखते थे । राजा नवाब भी जानते थे कि अंग्रेज बड़े कमीने हैं, लेकिन वह मजबूर थे। जमीदार, जागीरदार और बुद्धिजीवियों को उन्होंने राय बहादुर और सर जैसी उपाधियाँ देकर अपने पक्ष में किया। पुराना जमाना था उस समय पद्मश्रियाँ नहीं होती थी। पूरा देश अंग्रेजों से नफरत करता था लेकिन अब उनकी ताकत पहले से बढ़ गई थी। सरकार का खजाना खचाखच भरा हुआ था। उनके पास बड़ी सेना और लाखों मुलाजिम थे, और अपने कानून भी। इतने बड़े संगठन के साथ जमी हुई सरकार को हिलाना नामुमकिन था। लेकिन आम राय यही थी कि अंग्रेज बड़े कमीने हैं। अंग्रेजों के प्रति इस धारणा ने धीरे-धीरे अपना काम शुरू किया और देश की गरीब अनपढ़ और संगठित जनता ने एक स्वर में कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। इतिहास गवाह है, संघर्ष लंबा चला लेकिन कमीनों को भारत छोड़ना पड़ा। एक बार भागे अंग्रेज फिर कभी सत्ता में नहीं आ सके लेकिन उनका कमीनापन यहीं छूट गया । जय हिन्द ।

अतीत से अनुभव

चित्रा माली

सहायक प्रोफेसर गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विवि क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता

समाज को स्त्रियों के अनुकूल बनाने के प्रयत्न की दरकार

आर्कियोलॉजिकल मेथड में फूको ऐतिहासिक रूप से कैसे ज्ञान का निर्माण हुआ,उसका विश्लेषण करते हैं और इस विश्लेषण को इतिहास की शोध पद्धति से जोड़ते हुए फूको यह सूत्र प्रतिपादित करते हैं कि इतिहासकार को भी व्यक्ति केंद्रित विचारों के अध्ययन के बजाय विचार की ज्यादा बुनियादी और गहरी संरचनाओं की पड़ताल करनी चाहिए। जीनियोलॉजिकल मेथड में वे सत्ता संबंधों और सामाजिक संस्थाओं का ऐतिहासिक विश्लेषण करते हैं। एक व्यक्ति अपनी मर्जी के आधार पर दूसरे व्यक्ति से कुछ ऐसे कार्य करवा सकता है जो वह अन्यथा नहीं करता है तो इसे एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति पर सत्ता की संज्ञा दी जाएगी। सत्ता की यह सामान्य लगने वाली परिभाषा रॉबर्ट डाहल की दी हुई है।

नॉलेज इज पावर 'ज्ञान शक्ति है' इसका अभिप्राय यह है कि जिनके पास ज्ञान है उनके पास शक्ति या कहें सत्ता भी है और जिनके पास सत्ता है,वे ज्ञान का उत्पादन और नियंत्रण भी करते हैं। मिशेल फूको के अनुसार ज्ञान और शक्ति/सत्ता का अटूट संबंध है। जहां भी सत्ता या शक्ति केंद्रित होती है वहां उसका प्रतिकार करने के लिए प्रतिरोध भी होता है। सत्ता संबंधों में हमेशा एक संभावना होती है कि उन्हें चुनौती दी जाए और परिवर्तित किया जाए। सत्ता का प्रतिरोध केवल राजनीतिक आंदोलनों के रूप में वृहद स्तर पर ही न होकर व्यक्तिगत स्तर पर भी हो सकता है। फूको के शक्ति सिद्धांत के दो महत्वपूर्ण हिस्से है,पहला आर्कियोलॉजिकल और दूसरा जीनियोलॉजिकल मेथड है। आर्कियोलॉजिकल मेथड में फूको ऐतिहासिक रूप से कैसे ज्ञान का निर्माण हुआ,उसका विश्लेषण करते हैं और इस विश्लेषण को इतिहास की शोध पद्धति से जोड़ते हुए फूको यह सूत्र प्रतिपादित करते हैं कि इतिहासकार को भी व्यक्ति केंद्रित विचारों के अध्ययन के बजाय विचार की ज्यादा बुनियादी और गहरी संरचनाओं की पड़ताल करनी चाहिए। जीनियोलॉजिकल मेथड में वे सत्ता संबंधों और सामाजिक संस्थाओं का ऐतिहासिक विश्लेषण करते हैं। एक व्यक्ति अपनी मर्जी के आधार पर दूसरे व्यक्ति से कुछ ऐसे कार्य करवा सकता है जो वह अन्यथा नहीं करता है तो इसे एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति पर सत्ता की संज्ञा दी जाएगी। सत्ता की यह सामान्य लगने वाली परिभाषा रॉबर्ट डाहल की दी हुई है। यह केवल व्यक्तियों के संदर्भ में ही कारगर साबित होती है, समूह और सामूहिकता पर लागू करने पर इसमें कई सवाल खड़े हो जाते हैं। सामूहिक संदर्भ में सत्ता का आशय ऐसे निर्णय करने से है जिन्हें मानने के लिए दूसरे लोग मजबूर हों। समाज के संदर्भ में सत्ता किसके पास रहती है, किसके पास रहनी चाहिए और किस आधार पर उसका उपयोग किया जाना चाहिए? सत्ता समाज में समान रूप से वितरित है या किसी शासक वर्ग या किसी 'पॉवर इलीट' के हाथों में केंद्रित है? सत्ता से जुड़े ये प्रश्न इसलिए आवश्यक हो जाते हैं क्योंकि भारतीय समाज व्यवस्था पितृसत्तात्मक है। पितृसत्ता की अवधारणा प्रभुत्व की एक ऐसी सर्वव्यापी संरचना है जो हर स्तर पर काम करती है। पितृसत्ता की कोई एक समान संरचना नहीं होती है। इतिहास, भूगोल और संस्कृति के मुताबिक उसके भिन्न भिन्न रूप मिलते हैं। इसके अलावा पितृसत्ता शोषण और प्रभुत्व के अन्य रूपों (वर्ग,जाति, धर्म,नस्ल आदि) के साथ परस्पर व्यापी भी है। एक उच्च वर्ग की स्त्री और निम्न वर्ग स्त्री को इस व्यवस्था में उत्पीड़न और शोषण को अलग-अलग प्रकार से झेलने पड़ते हैं। सत्ता से पितृसत्ता तक इस विमर्श को जोड़ने का कारण स्त्रियों को सत्ता से और खासकर ज्ञान की सत्ता से दूर रखे जाने की साजिश से भी परिचित करवाना था जो कहीं न कहीं भय से ग्रसित थी। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था। इनके पिता का नाम खन्दोजी नैवेसे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। सावित्रीबाई फुले का विवाह महज 10 वर्ष की उम्र में 1841 में ज्योतिबा फुले से हुआ था। सावित्रीबाई प्रारंभ से ही पढ़ना और लिखना चाहती थी लेकिन उस समय स्त्रियों का पढ़ना और खासकर निम्न जाति की स्त्रियों का पढ़ना अपराध की श्रेणी में आता था। इसलिए वे अपने पिता के घर में अक्षर ज्ञान भी न ले सकीं। विवाह के पश्चात सावित्री बाई को ज्योतिबा फुले ने पढ़ाया और उन्हें पहली महिला शिक्षिका भी बनाया ताकि अन्य महिलाएं भी ज्ञान से वंचित न रहें।

1848 में पुणे के बुधवार पेठ में सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले ने डिप्रेस्ड क्लास के बच्चों के लिए एक विद्यालय आरंभ किया । इसके पूर्व जो विद्यालय थे वो प्रिविलेज तबके के लिए ही थे । सावित्रीबाई फुले इस विद्यालय की प्रथम शिक्षिका बनी । 3 जुलाई 1857 को फुले दंपति ने पहले बालिका विद्यालय का शुभारंभ किया था। उस समय स्त्री शिक्षा के विरोध में एक प्रिविलेज तबका भी था जो नहीं चाहता था कि महिलाएं और बालिकाएं शिक्षित हों तथा महिलाओं की सामाजिक हैसियत में कोई बदलाव आए,वहीं विद्यालय के लिए जमीन देने वाले और सहयोग करने वालों की भी कमी नहीं थी। पहले बालिका विद्यालय की जमीन अन्ना साहब चिपलूणकर जी के द्वारा दी गई थी जो प्रिविलेज तबके

से होने के बावजूद भी फुले दंपत्ति का सहयोग कर रहे थे। दूसरे विद्यालय के लिए जमीन फातिमा शेख ने उपलब्ध करवाई जिन्होंने छात्रा और शिक्षिका दोनों की भूमिका निभाई। सावित्रीबाई फुले जब अपने घर से विद्यालय बालिकाओं को पढ़ाने के लिए जाती थीं तब उन पर स्त्री शिक्षा के विरोधियों द्वारा कचरा,गोबर व पत्थर भी फेंके जाते थे,वे अपने साथ एक थैली में दूसरी साड़ी भी रखती थीं जिसे विद्यालय में वह बदलकर अध्यापन का कार्य करती थी। तमाम विरोधों और अवरोधों के बाद भी सावित्रीबाई फुले ने स्त्रियों की शिक्षा और अधिकारों के लिए प्रयास जारी रखे। भारत में फुले दंपत्ति स्त्री-शिक्षा,स्त्री पुरुष समानता,अंधविश्वासों व कर्मकांडों से मुक्ति के प्रयास तथा सामाजिक कुरीतियां बाल- विवाह,जाति व्यवस्था,छुआछूत, पर्दा प्रथा के विरुद्ध भी संघर्ष कर रहे थे। डिप्रेस्ड क्लास को न्याय दिलाने के लिए फुले दम्पत्ति ने 1873 में 'सत्यशोधक समाज' की स्थापना की जिससे लोगों में फैले अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों को समाप्त किया जा सके। स्त्रियों को शिक्षित करने में सावित्री बाई फुले ने महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सावित्री बाई फुले ने अपनी कविताओं के माध्यम से भी पितृसत्तात्मक व्यवस्था का प्रतिरोध भी किया था। आज जब हम सावित्री बाई फुले पर बात कर रहे हैं,उनके प्रयासों और उन प्रयासों में आने वाली बाधाओं और कठिनाईयों को देख रहे हैं तो कहीं न कहीं समाज को सामाजिक परिस्थितियों को फ्लैशबैक (पूर्व-दृश्य) में देखने का कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार से सिनेमा में फ्लैशबैक से थोड़ी देर के लिए पर्दे पर दिखाई जा रही तस्वीरों को वर्तमान से अतीत में स्थानांतरित कर देता है। समाज सुधार की फिल्मों में स्थापित मूल्यों पर सवालिया निशान लगाने के लिए फ्लैशबैक का प्रयोग किया जाने लगा। यह परंपरा के बरक्स आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में उसका योगदान था। आधी सदी के बाद जब राष्ट्र और व्यवस्था की रचना एक सीमा तक पूरी हो गई तो उसने राजनीतिक और प्रशासनिक मूल्यों की आलोचना के लिए बनायी गयी फिल्मों में भी फ्लैशबैक की तकनीक का रचनात्मक इस्तेमाल करके भी दिखाया है। इस क्रम में अगर 'फुले' फिल्म पर बात करे जिसमें अतीत के लिए फ्लैशबैक का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इतिहास को,सामाजिक व्यवस्था को तमाम विषमताओं से भरा दिखाने का प्रयास किया गया है जैसा वह था। लेकिन अतीत की इन सामाजिक विषमताओं से शर्मसार होने के बजाए इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की गई। जिससे फिल्म को प्रदर्शित होने में विलंब भी हुआ।

इस पूरे प्रकरण में फ्लैशबैक के जरिए वर्तमान अतीत में नहीं लौटता बल्कि अतीत वर्तमान में लौट आता है। एक तरह से यह रिवर्स-फ्लैशबैक है। क्योंकि आज भी समाज व्यवस्था एक ही वर्ग से संचालित हो रही है उसमें थोड़ी बहुत रियायतें अवश्य दिखाई देती है लेकिन मूल चरित्र व स्वरूप पूर्व की भांति ही है। जातिगत संरचना और ज्यादा जटिल हुई है इसके प्रमाण अखबारों में हर रोज प्रकाशित होते हैं और ज्ञान भी एक वर्ग तक ही सीमित रहे इसके भी प्रयास जारी है। इसलिए आवश्यक है कि हम स्त्री शिक्षा के लिए सावित्री बाई फुले के प्रयासों व योगदानों का सिर्फ उल्लेख न करें बल्कि उनकी मूल प्रस्तावनाओं को आत्म सात कर सामाजिक कुरीतियों को मिटाने का भी प्रयास करें।

आज स्त्रियों का एक छोटा सा तबका ही ज्ञान की इस सत्ता को सेलिब्रेट कर अपनी स्वतंत्रता और निर्णय लेने के अपने अधिकार को दर्ज करा रहा है जबकि स्त्रियों का एक बहुत बड़ा भाग आज भी ज्ञान की सत्ता से महरूम है और किसी न किसी पर आश्रित हो जीवनयापन कर रही है। स्त्री शिक्षा और स्त्री संघर्ष ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इसी की बदौलत ही स्त्री मुखर हो बोल, लिख और पढ़ पा रही है। आज आवश्यकता ऐसी कई और स्त्रियों की है जो मुखर हो अपने साथ हुई नाइंसाफियों और गैरबराबरी के खिलाफ मुहिम छेड़ दे। जिससे आने वाले समय और समाज को स्त्रियों के अनुकूल बनाया जा सके और वो पितृसत्ता की घिसीपिटी रूढ़ियों से स्वतंत्र हो तथा स्त्रियों के स्वतंत्र विकास में सहायक सिद्ध हो।

तंत्र

राजेन्द्र जोशी

लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।

प्रदूषित जल की घंटी तो कब की बज चुकी

इंदौर के भागीरथ पुरा में दूषित जल की घटना ने देश के सबसे स्वच्छ शहर का कई सालों तक तमगा हासिल करने वाले शहर नागरिकों को भी शर्मशार कर दिया.दूषित जल से मरने वाले परिवारों का दुख किसी संवेदना या मुआवजे से कम नहीं हो सकता,नहीं जाने वाला परिवार का सदस्य लोट सकता है,लेकिन जांच इमानदारी से होना चाहिए । गत वर्ष दिवाली पर्व के दौरान बड़वानी जिला मुख्यालय के नजदीकी ग्राम सजवानी के ग्रामवासियों की दिवाली अस्पताल में बीत गई जब दूषित जल से गांव के लगभग दो सैकड़ा लोग उल्टी दस्त की चपेट में आ गये, मीडिया ख़बरों के बाद प्रशासन जागा और गाज गिरी ग्राम पंचायत के सचिव पर,जबकि ग्राम के एक जिम्मेदार नागरिक ने घटना के पंद्रह दिन पूर्व ग्राम पंचायत को नलों में दूषित पानी आने की लिखित में सूचना दे दी थी,लेकिन पंचायत कोई भी कार्यवाही कर पाने में असमर्थ साबित हुई.

वह दिन दूर नहीं जब मप्र के हर गांव,नगर में जल प्रदूषण की गूंज सुनाई देने लगे, जल प्रदूषण के खतरे की घंटी तो 2025 की धनतेरस के दिन ही मप्र के बड़वानी जिले के ग्राम सजवानी में बज गई थी जब दीपावली के पूर्व गांव के सैकड़ों निवासी दूषित जल पीने से बीमार हो गये थे, सजवानी की घटना बड़ा सबक थी, अगर समय रहते जाग जाते तो हादसे को टाला जा सकता था, लेकिन मप्र में जल नल और सीवरेज का काम करने वाली ठेकेदार फ़र्मो पर नौकरशाह तो दूर जन प्रतिनिधी तक मुँह नहीं खोल सकते जनता की बात ही छोड़ दो वह तो राजनीतिक खेमों में बंटी होने के साथ उन्ही पर आश्रित नजर आती है.

इंदौर के भागीरथ पुरा में दूषित जल की घटना ने देश के सबसे स्वच्छ शहर का कई सालों तक तमगा हासिल करने वाले शहर नागरिकों को भी शर्मशार कर दिया.दूषित जल से मरने वाले परिवारो का दुख किसी संवेदना या मुआवजे से कम नहीं हो सकता,नहीं जाने वाला परिवार का सदस्य लोट सकता है,लेकिन जांच इमानदारी से होना चाहिए ।

गत वर्ष दिवाली पर्व के दौरान बड़वानी जिला मुख्यालय के नजदीकी ग्राम सजवानी के ग्रामवासियों की दिवाली अस्पताल में बीत गई जब दूषित जल से गांव के लगभग दो सैकड़ा लोग उल्टी दस्त की चपेट में आ गये, मीडिया ख़बरों के बाद प्रशासन जागा और गाज गिरी ग्राम पंचायत के सचिव पर,जबकि ग्राम के एक जिम्मेदार नागरिक ने घटना के पंद्रह दिन पूर्व ग्राम पंचायत को नलों में दूषित पानी आने की लिखित में सूचना दे दी थी, लेकिन पंचायत कोई भी कार्यवाही कर पाने में असमर्थ साबित हुई.

ग्रामवासी गणेश परमार ने बताया कि गाँव में दस्त लगने की समस्या धनतेरस 18 अक्टूबर 2025 से शुरु हुई जो अगले 02 दिनों में 6000 की जनसंख्या वाले गाँव मेंकरीब 200 लोग इसकी चपेट में आ गये।

जल जीवन मिशन की वेबसाईट पर 02 सितंबर 2025 की पानी की रिपोर्ट में टर्बिडिटी (मटमैलापन) की उपस्थिति इस बीमारी का कारण हो सकती है। मटमैले पानी में मिट्टी के कणों के साथ बैक्टीरिया और वायरस जैसे रोगवाहक भी शामिल होते हैं। हालांकि रिपोर्ट में

दिखाई दे रही है टर्बिडिटी स्वीकार्य मात्रा में थी लेकिन शिकायत के बावजूद इस पर रोक लगाने का कोई प्रयास दिखाई नहीं दिया। संभवत इसी लापरवाही ने ग्रामीणों की दीवाली काली कर दी।

जब इस मामले की पड़ताल हुई तो पता चला गांव की जल नल योजना की पाइप लाइन गंदे नाले से होकर गुजर रही थी,उसमे लगे पानी के वालो से होने वाली लिकेजेंगी के साथ पानी के लगे वाल बक्सों की सफाई नहीं होने से गंदे पानी का स्वच्छ पानी में मिलने से ये घटना घटित हुई.इसी गांव के पास स्थित बालकुआ गांव में कोई हादसा नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ की पाइप लाइन के हाल सजवानी ग्राम जैसे ही हैं.

यही हाल उन ग्रामों में दिखाई दे रहा है जहां पर जल जीवन मिशन के तहत जल प्रदाय की योजना संचालित हो रही है,बड़वानी जिले के ही विश्वनाथ खेड़ा गांव के लोग पाइप लाइन लीकेज की कई बार शिकायत कर चुके है लेकिन न तो विभाग जागा न कोई कार्यवाही हुई.

जल जीवन मिशन के अंतर्गत देशभर के साथ मप्र में लगाई जा रही जल नल योजना का कार्य करने वाले ठेकेदार इतने रसूख वाले है कि विभाग तक उन पर कार्यवाही करने से घबराता है,बड़वानी जिले के दस गाँवों में जल नल योजना का कार्य करने वाले एक ठेकेदार के द्वारा चार गाँवो में गुणवत्ता विहीन पाइप लगाने की बात शपथ पत्र पर स्वीकार कर लेने के बाद भी विभाग और जिल प्रशासन उस पर कार्यवाही नहीं कर पाया,जबकि इसी ठेकेदार को धार जिले में विभाग ने काली सूची में डाल दिया था.

जल नल योजना व सीवरेज योजना के चलते गांव गांव,नगर दर नगर में लाइनें डल रही है,कार्य की समय सीमा पूरा करने की जल्दी के चलते कार्यो में लापरवाही व गुणवत्ता विहीन सामग्री के साथ सर्वत्र चुप्पी याने कोई विरोध न होना ही घटनाओं के रूप में सामने आ रहे है.

गौरतलब है कि हम उसी मप्र के वाशिन्दे है,जहां सालो से इन्दौर के गन्दे पानी वाली खान नदी के पानी को क्षिप्रा नदी का जल समझ कर कई बार आचमन, स्नान पूजन कर चुके है (यह बात और है कि अवसरो पर क्षिप्रा नदी में नर्मदा नदी का जल छोडा जाता है)।

यात्रा

कुमार सिद्धार्थ

लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।

गांधी तीर्थः तकनीक और विचार से जुड़ने का अद्भुत अनुभव

हिंसा, असहिष्णुता और वैचारिक विभाजन के इस दौर में महात्मा गांधी को नए सिरे से समझने की ज़रूरत और गहरी हो जाती है। महाराष्ट्र के जलगांव में स्थित 'गांधी तीर्थ' इसी तलाश का उत्तर देता है। यह स्थल हमें बताता है कि गांधी को समझना केवल किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि उनके विचारों से सीधे जुड़ने की एक जीवंत प्रक्रिया है।

आधुनिक तकनीक, शोधपूर्ण प्रस्तुति और संवेदनशील क्यूरेशन के माध्यम से 'गांधी तीर्थ' महात्मा गांधी के जीवन, संघर्ष और मूल्यों को जिस तरह सजीव करता है, वह इसे एक साधारण दर्शनीय स्थल से कहीं आगे ले जाता है।

'गांधी तीर्थ' का बड़ा आकर्षण यह है कि यह महात्मा गांधी को केवल 'महापुरुष' के रूप में नहीं, बल्कि मोहनदास करमचंद गांधी एक जिज्ञासु बालक, प्रयोगशील युवा, संघर्षरत वकील और सतत साधक के रूप में सामने रखता है। इस तीर्थ की सबसे अनोखी विशेषता इसकी ऑडियो गाइड तकनीक है। हेडफोन के माध्यम से जैसे ही हम एक-एक खंड में प्रवेश करते हैं, गांधी का जीवन, उनके विचार और उनके समय की परिस्थितियाँ हमारे भीतर उतरने लगती हैं। यह यात्रा पोरबंदर के एक सामान्य से घर से शुरू होकर दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह और भारत के स्वतंत्रता संग्राम तक पहुँचती है।

महात्मा गांधी के जीवन कार्यों पर आधारित विश्व का पहला आडियो गाइडेड संग्रहालय भ्रमण के अनुभव को विशेष बनाती हैं। यह साधारण जानकारी नहीं होती, बल्कि एक तरह का संवाद है, जो दर्शक को भीतर तक छू लेता है। आवाज़, संगीत, ऐतिहासिक उद्धरण और दृश्य एक साथ मिलकर ऐसा अनुभव रचते हैं कि दर्शक केवल देख नहीं रहा होता, बल्कि उस समय को जी रहा होता है। यह तकनीक गांधी के विचारों से भावनात्मक और बौद्धिक दोनों स्तरों पर जोड़ देती है।

संग्रहालय के 31 से अधिक खंड टच स्क्रीन, बाइस्कोप, डिजिटल बुक्स, थ्री-डी मैपिंग, एनिमेशन, ऐतिहासिक तस्वीरें, दुर्लभ फुटेज, गांधी के भाषणों की आवाज़ और समकालीन घटनाओं का दृश्यांकन आदि सब मिलकर ऐसा वातावरण रचते हैं, मानो इतिहास किताबों से निकलकर हमारे सामने खड़ा हो गया हो। चरखा, नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन ये सब केवल घटनाएँ नहीं रह जातीं, बल्कि मानवीय संवेदना और नैतिक साहस की कहानियाँ बन जाती हैं। इन प्रस्तुतियों में भावुकता नहीं, बल्कि विचार की स्पष्टता और संदर्भ की गहराई दिखाई देती है।

'गांधी तीर्थ' में यह बात बार-बार उभरकर आती है कि गांधी का जीवन किसी एक दिन, एक घटना या एक आंदोलन से परिभाषित नहीं होता। उनका जीवन सतत प्रयोगों की प्रयोगशाला था सत्य के प्रयोग, अहिंसा के प्रयोग, आत्मसंयम और सामाजिक न्याय के प्रयोग। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ उनके संघर्ष से लेकर भारत में किसानों, मजदूरों और महिलाओं के प्रश्नों तक–हर जगह गांधी का आग्रह एक ही रहा- साधन की पवित्रता और साध्य की नैतिकता।

गांधी तीर्थ यह भी स्पष्ट करता है कि गांधी के लिए राजनीति सत्ता का खेल नहीं, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी थी। सत्य, अहिंसा, आत्मसंयम और करुणा ये उनके लिए नारे नहीं, जीवन की पद्धति थे। प्रदर्शनी में यह बात उभरकर आती है कि गांधी के प्रयोग केवल स्वतंत्रता आंदोलन तक सीमित नहीं थे, बल्कि शिक्षा, समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण तक फैले हुए थे। यहाँ यह

भी प्रभावी ढंग से दिखाया गया है कि गांधी केवल राजनीतिक नेता नहीं थे, बल्कि समाज सुधारक, शिक्षाविद और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील चिंतक भी थे। बुनियादी शिक्षा, स्वदेशी, ग्राम स्वराज और श्रम की गरिमा–इन विचारों को आज की चुनौतियों से जोड़कर प्रस्तुत किया गया है।

डिजिटल माध्यमों से यह सवाल भी उठाया जाता है कि उपभोक्तावाद, हिंसा और असमानता से भरी आज की दुनिया में गांधी की प्रासंगिकता कहाँ और कैसे है। इन सवालों के सीधे उत्तर नहीं दिए जाते, बल्कि दर्शक को सोचने के लिए प्रेरित किया जाता है और शायद यही गांधी की सबसे बड़ी शिक्षा है।

'गांधी तीर्थ' का एक सशक्त पक्ष यह भी है कि यहाँ महात्मा गांधी के साथ उनके समय के अन्य व्यक्तित्वों और आंदोलनों का संदर्भ भी मिलता है। गोखले, टॉलस्टॉय, टैगोर, नेहरू इन सबके साथ गांधी का संवाद और मतभेद ईमानदारी से प्रस्तुत किए गए हैं। इससे गांधी किसी देवतुल्य, आलोचना से परे छवि में नहीं, बल्कि एक विचारशील और आत्मालोचन करने वाले मनुष्य के रूप में उभरते हैं।

भ्रमण के दौरान सबसे गहरा प्रभाव गांधी के नैतिक साहस ने छोड़ा। सत्ता, लोकप्रियता या तात्कालिक लाभ के आगे झुकने से इनकार करने का साहस आज के समय में दुर्लभ होता जा रहा है। 'गांधी तीर्थ' यह याद दिलाता है कि परिवर्तन की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। सत्य और अहिंसा केवल राजनीतिक रणनीति नहीं, बल्कि जीवन जीने की पद्धति हैं।

'गांधी तीर्थ' लगभग 40 एकड़ में फैला हुआ एक विस्तृत और शांत परिसर है। हरियाली, खुले स्थान और सादगी से भरा यह वातावरण स्वयं गांधी के जीवन-दर्शन की याद दिलाता है। यह परिसर बीते करीब दो दशकों से सक्रिय है और गांधीवादी विचारों के अध्ययन, शोध और प्रसार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। पद्मश्री डॉ. भंवरलाल जैन के अथक परिश्रम और उनके अदभुत कल?पना का साकार रूप लेता गांधी रिसर्च फाउंडेशन न केवल गांधी के जीवन और कर्म पर कार्य कर रहा है, बल्कि गांधी के विचारों को समकालीन संदर्भों से जोड़ने का भी सतत प्रयास कर रहा है, जहां गांधी के विविध रचनात्मक कार्यों को धरातल पर उतरते आप देख सकते है।

यह भी उल्लेखनीय है कि गांधी तीर्थ केवल अतीत की ओर देखने वाला स्थल नहीं है। यहाँ शोध, अध्ययन और संवाद के लिए व्यापक संसाधन उपलब्ध हैं। यह स्थान युवाओं, शोधकर्ताओं और शिक्षकों के लिए प्रेरणा का केंद्र बन सकता है। यहाँ से निकलते समय मन में यह भाव बना रहता है कि गांधी को 'पढ़' लेने से अधिक ज़रूरी है उन्हें 'जीना'–अपने छोटे-छोटे निर्णयों, व्यवहार और सामाजिक जिम्मेदारियों में।

आज जब समाज हिंसा, नफरत, संप्रदायिकता, असहिष्णुता और पर्यावरणीय संकटों से जूझ रहा है, तब गांधी तीर्थ हमें यह याद दिलाता है कि समाधान कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर मौजूद नैतिक विवेक में छिपा है। यही इस तीर्थ की सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे गहरी सीख है। यहाँ आकर यह सवाल बार-बार मन में उठता है कि क्या इन समस्याओं का समाधान केवल कानून और शक्ति में है, या फिर नैतिक विवेक और संवाद में गांधी तीर्थ यह जरूर रास्ता दिखाता है कि अहिंसा, सह-अस्तित्व और सत्य के मार्ग पर चलकर विकल्प खोजे जा सकते हैं।

इस अर्थ में गांधी तीर्थ केवल अतीत का संग्रहालय नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए एक वैचारिक प्रयोगशाला है। यदि आज की दुनिया में बढ़ती हिंसा और संप्रदायिकता का कोई टिकाऊ समाधान तलाशना हो, तो गांधी तीर्थ की यात्रा आवश्यक लगती है। यहाँ से लौटते समय यह एहसास गहरा हो जाता है कि गांधी कोई इतिहास का अध्याय नहीं, बल्कि हमारे समय की ज़रूरत हैं–और उन्हें समझने की शुरुआत यहीं से हो सकती है।

जनसंवाद से समाधान तक सांसद सावित्री ठाकुर की सक्रिय पहल

केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर ने धार में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित कर नागरिकों से जानी समस्याएं

धार। लोकसभा क्षेत्र धार डूमहू की सांसद एवं केंद्रीय राज्यमंत्री महिला एवं बाल विकास सावित्री ठाकुर द्वारा आमजन से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु 5 जनवरी सोमवार को जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम दो सत्रों में संपन्न हुआ, जिसमें दूर-दूर से आए कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों एवं आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष महंत निलेश भारती ,भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ शरद विजयवर्गीय विशेष रूप से उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के प्रथम सत्र में प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय धार में सांसद सावित्री ठाकुर ने आमजन, पार्टी कार्यकर्ताओं एवं जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। इस दौरान क्षेत्र की जनसमस्याओं, विकास कार्यों की प्रगति, केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तथा स्थानीय आवश्यकताओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

द्वितीय सत्र दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक सांसद जनसंवाद केंद्र, रोटरी क्लब के सामने स्थित कार्यालय पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर नागरिकों द्वारा व्यक्तिगत एवं सामूहिक समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए गए। जनसंवाद कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य सहायता, सड़क निर्माण, आगजनी से हुए आर्थिक नुकसान, बिजली आपूर्ति संबंधी समस्याएं, बच्चों की गंभीर एवं लाइलाज बीमारियों हेतु सहायता, आंगनवाड़ी भवन निर्माण तथा कपास किसानों से जुड़ी समस्याओं के

आवेदन मुख्य रूप से प्राप्त हुए।

भाजपा जिला मीडिया प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि इसी क्रम में ग्राम पंचायत केसरपुरा तेली के ग्राम रालामंडल के ग्रामीणों द्वारा नालावाड़ा तक के मार्ग को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत जोड़ने की महत्वपूर्ण मांग रखी गई। ग्रामीणों की इस आवश्यक मांग पर मंत्री ठाकुर ने तत्काल संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संबंधित अधिकारियों से दूरभाष पर चर्चा की, जिसके परिणामस्वरूप उक्त सड़क मार्ग की स्वीकृति प्राप्त हो गई। सड़क की स्वीकृति से ग्रामवासियों में हर्ष का वातावरण है तथा क्षेत्र में आवागमन सुगम होने के साथ विकास को नई गति मिलेगी।

श्रीमती ठाकुर ने प्राप्त सभी आवेदनों पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए तत्काल संबंधित अधिकारियों से दूरभाष पर चर्चा की एवं कई मामलों में मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आमजन की समस्याओं का शीघ्र निराकरण उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

धार लोकसभा क्षेत्र से लेकर भोपाल स्तर तक तथा राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों के प्रमुख सचिवों से सीधा संवाद कर आमजन एवं कार्यकर्ताओं की समस्याओं के निवारण हेतु सार्थक पहल की गई।

सावित्री ठाकुर ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए जनसंवाद जैसे कार्यक्रम अत्यंत आवश्यक हैं। आमजन की आवाज को सीधे सुनना, उनकी अपेक्षाओं को समझना तथा विकास कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाना ही इस पहल का मूल उद्देश्य है। उन्होंने उपस्थित नागरिकों एवं कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए आश्वस्त किया कि प्रत्येक समस्या का समाधान समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से किया जाएगा।

साथ ही जानकारी दी गई कि आगामी 7 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में मंत्री दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कार्यालय में प्रातः 11 बजे से सायं 5 बजे तक उपस्थित रहेंगे, जहां देशभर से आने वाले कार्यकर्ताओं एवं आमजन से भेंट कर उनकी समस्याओं को सुना जाएगा।

श्रीमती ठाकुर ने क्षेत्र के समस्त नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों एवं पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे जनसंवाद कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता कर क्षेत्र के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। यह जनसंवाद कार्यक्रम जनप्रतिनिधि और जनता के बीच विश्वास, पारदर्शिता एवं सहभागिता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुआ है।

दो दिवसीय अग्रवाल युवक-युवती परिचय सम्मेलन धार में 10 जनवरी से

समाजजनों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सम्मेलन स्थल पर किया भूमिपूजन

धार। मध्यप्रदेश अग्रवाल महासभा धार द्वारा अग्रवाल समाज धार के सानिध्य में दो दिवसीय आयोजित अखिल भारतीय विवाह योग्य युवक-युवतियों का परिचय सम्मेलन धार स्थित श्रद्धा शगुन गार्डन में 10 से 11 जनवरी को होगा। सोमवार को सुबह अग्रवाल युवक युवती परिचय सम्मेलन के पदाधिकारियों की मौजूदगी में गणेश जी महालक्ष्मी जी,महाराजा अग्रसेन जी का पूजन कर पंडित नरोत्तम मिश्र तनु महाराज के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया गया। सम्मेलन स्थल पर आयोजन समिति के मुख्य संयोजक बबनलाल अग्रवाल,अनन्त अग्रवाल, मनोहरलाल अग्रवाल, सयोंजक गोपीकिशन अग्रवाल,डॉ उमेश मित्तल, राजेंद्र मोदी डॉ. के.सी जिंदल के मुख्य आतिथ्य में भूमि पूजन किया।

सभी ने संकल्प किया कि वे दो दिवसीय इस परिचय सम्मेलन में समाज स्तर पर अधिक से अधिक रिश्ते तय कराने और अन्य व्यवस्थाओं में भी भागीदार रहेंगे। प्रत्याशियों एवं पालकों के स्वागत हेतु मालवा की परंपरानुसार व्यवस्था की गई है। सम्मेलन स्थल पर चाय एवं स्वल्पाहार के अलावा समुचित भोजन की भी व्यवस्था रखी गई है। सम्मेलन का शुभारंभ सुबह ठीक 11 बजे होगा और शुभारंभ समारोह के तुरंत बाद परिचय की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस अवसर पर घनश्याम अग्रवाल आलू वाले,कैलाश मालक,सतीश अग्रवाल गुणावद, बंसीधर अग्रवाल, ओमप्रकाश अग्रवाल,

आशीष गोयल, मुरली अग्रवाल, पराग अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, विमल गर्ग, सतीशचंद्र अग्रवाल जीजा, अनिल गुप्ता, मनीष गुप्ता, मनीष अग्रवाल,महेश अग्रवाल, ओमप्रकाश अग्रवाल, घनश्याम मित्तल, कमल मिर्जापुर, रितेश अग्रवाल,बृजेश अग्रवाल, शोभा अग्रवाल, कुसुम अग्रवाल रेनू अग्रवाल, कविता अग्रवाल, रीना गोयल, पायल गोयल, अनीता अग्रवाल,भावना गुप्ता, राहुल अग्रवाल, पार्थ गोयल, प्रचुर गर्ग सहित बड़ी संख्या में समाज बंधु, मातृशक्ति और युवा उपस्थित थे। जानकारी मीडिया प्रभारी अशोक मित्तल एवं श्याम मंगल लेबड़ ने दी।

शासकीय आयुर्वेद जिला चिकित्सालय में भर्ती रोगियों के लिए भोजन व्यवस्था प्रारंभ

बैतूल। शासकीय आयुर्वेद जिला चिकित्सालय टिकारी बैतूल में भर्ती रोगियों के लिए भोजन व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई है। जिला आयुष अधिकारी डॉ. योगेश चौकीकर ने बताया कि चिकित्सालय के अंतरंग रोगी विभाग में अब मरीजों को आयुर्वेद विशेषज्ञों की सेवाओं के साथ नियमित भोजन सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। चिकित्सालय में एमडी पंचकर्म डॉ. नरेंद्र डडोरे, डॉ. रीना चौकीकर एमएस, नाक-कान-गला एवं मर्म चिकित्सा डॉ. निधि मालवीय द्वारा निरंतर उपचार किया जा रहा है। इसके अलावा बाल्य रोग डॉ योगेश चौकीकर, शल्य चिकित्सा डॉ रवि चौकीकर एवं काय चिकित्सा डॉ प्रियंका भी अपनी सेवाएं दे रही हैं।

ग्रामीण मरीजों को मिलेगा 24 घंटे लाभ

डॉ.चौकीकर ने बताया कि ग्रामीण अंचल से आने वाले पंचकर्म रोगियों को अब तक रोज आना-जाना करना पड़ता था। रुकने व भोजन की सुविधा शुरू होने से वे अब चिकित्सालय में ठहरकर नियमित उपचार कर सकेंगे। आयुर्वेद चिकित्सालय में नवाचार के तहत गर्भ संस्कार की सुविधा दी जा रही है। 6 माह से 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रत्येक पुष्य नक्षत्र के दिन स्वर्ण प्राशन कराया जा रहा है। महिला व पुरुष पंचकर्म की अलग-अलग इकाइयां संचालित हैं। साथ ही योग प्रशिक्षक द्वारा प्रतिदिन प्रातःकाल रोगानुसार योग, ध्यान एवं सरल योग क्रियाएं कराई जा रही हैं। उन्होंने जिले वासियों से अपील की है कि वे आयुर्वेद जिला चिकित्सालय में उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाएं।

छात्रावासों के बिजली बिलों में 40 लाख का गबन

कंप्यूटर ऑपरेटर सहित दो पर एफआईआर, तीन कर्मचारी निलंबित

बैतूल। जनजातीय कार्य विभाग के छात्रावासों के बिजली बिलों में 40 लाख से अधिक के गबन के मामले में सोमवार बैतूल जनपद के एक कर्मचारी समेत दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने कंप्यूटर ऑपरेटर छत्रपाल मर्सकोले और धर्मेंद्र वरकड़े के खिलाफ धारा 420 और 409 भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया है। यह पूरा मामला जनपद पंचायत बैतूल में जनजातीय कार्य विभाग के छात्रावासों के विद्युत बिल भुगतान से संबंधित है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि वर्ष 2021 से 2025 के बीच कार्यालय में पदस्थ कंप्यूटर ऑपरेटर छत्रपाल मर्सकोले ने आईएफएमआईएस पोर्टल पर डीडीओ लॉगिन का दुरुपयोग किया। ऑपरेटर ने फर्जी वेंडर बनाए और उनके माध्यम से विद्युत विभाग के नाम पर राशि निजी बैंक खातों में स्थानांतरित की। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि कई मामलों में दोहरे भुगतान किए गए एक बार वास्तविक विद्युत विभाग के खाते में और दूसरी बार इन फर्जी खातों में। बैंक खातों की पुष्टि से पता चला कि वे विद्युत विभाग से संबंधित नहीं थे, बल्कि स्थानीय व्यक्तियों के थे। इनमें से कुछ खातों में आरोपी ऑपरेटर द्वारा यूपीआई के माध्यम से भी राशि ट्रांसफर की गई थी। प्रशासनिक जांच में आरोपी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। इसके बाद जनपद पंचायत सीईओ शिवानी राय ने रिपोर्ट जिला पंचायत सीईओ अक्षत जैन को भेजी। जांच में कुल 40,04,067 के गबन की पुष्टि हुई, जिसमें से 5.24 लाख सरकारी खाते में वापस जमा कराए जा चुके हैं।

पाले से फसलों की सुरक्षा के लिए कृषि विभाग ने जारी की सलाह

बैतूल। जनवरी माह में शीतलहर का दौर शुरू है। शीतलहर के कारण पौधे की पत्तियां व फूल झुलसते, बाद में झड़ जाते हैं। ऐसे में कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे पाले से फसलों की सुरक्षा एवं सर्तकता के लिए रात्रि में खेत की मेड़ों पर लगभग 6 से 8 स्थानो पर कचरा तथा खरपतवार आदि जलाकर धुंआ करें। यह प्रयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि धुआं सारे खेत में छा जाए तथा खेत के आसपास का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक आ जाए। धुआं करने से फसल का पाले से बचाव किया जा सकता है। पाले की संभावना होने पर खेत की हल्की सिंचाई कर देना चाहिए। इससे मिट्टी का तापमान बढ़ जाता है तथा नुकसान की मात्रा कम हो जाती है। सिंचाई बहुत ज्यादा नहीं करनी चाहिए तथा इतनी ही करनी चाहिए जिससे खेत गीला हो जाए। रस्सी का उपयोग भी पाले से काफी सुरक्षा प्रदान करता है। इसके लिए दो व्यक्ति सुबह-सुबह (जितनी जल्दी हो सके) एक लंबी रस्सी को उसके दोनों सिरों से पकड़ कर खेत के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक फसल को हिलाते चलना है। इससे फसल पर रात का जमा पानी गिर जाता है तथा फसल की पाले से सुरक्षा हो जाती है।

मामला सामने आने के बाद बैतूल नपा ने लिखा पत्र, समायोजित राशि लौटाने की मांग

चुंगी क्षतिपूर्ति राशि, अन्य नपा के देयकों के भुगतान में हो रही थी समायोजित

बैतूल। नगर पालिका परिषद बैतूल की चुंगी क्षतिपूर्ति राशि से अन्य नगर पालिकाओं के बिजली बिलों का समायोजन करने का मामला सामने आया है।पिछले 6-7 महीने या उससे भी अधिक सयम से यह राशि समायोजित हो रही थी। जब यह पूरा मामला सामने आया तो नगरपालिका बैतूल ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को पत्र लिखकर आपत्ति दर्ज कराई है और मामले की जांच की मांग की है। दरअसल नगरपालिका को प्रतिमाह चुंगी क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त होती है। यह राशि पिछले कई महीनों से अन्य नगरपालिकाओं के बिजली बिलों में समायोजित की जा रही थी। जिससे नगरपालिका को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। बताया जा रहा है कि इस राशि से संबंधित नगरपालिका के विद्युत देयकों की कटौती की जाती है। संचालनालय से नवंबर में बैतूल नगरपालिका को प्राप्त चुंगी क्षतिपुर्ति राशि से 60 लाख 4 हजार 534 रुपए के बिजली बिलों का समायोजन किया गया। जब इस समायोजन का बारीकी से अवलोकन किया, तो पता चला कि इसमें से 4 लाख 80 हजार 208 रुपए नगर पालिका परिषद आमला के उच्चदाब विद्युत कनेक्शन क्रमांक क्रमांक एच 2291038204 से संबंधित पाई गई। इस खुलासे के बाद नगर पालिका परिषद बैतूल ने इसे गंभीर वित्तीय अनियमितता बताते हुए विभाग का ध्यान आकर्षित किया है।

नियम विपरीत है चुंगी राशि का समायोजन

नगरपालिका बैतूल का कहना है कि चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि संबंधित निकाय के वित्तीय संचालन और नागरिक सुविधाओं के लिए निर्धारित होती है। इस राशि से किसी अन्य नगर पालिका के बिजली देयकों का समायोजन किया जाना न केवल नियमों के विपरीत है, बल्कि इससे बैतूल नगर पालिका की आर्थिक स्थिति पर भी

कई महीनो से हो रहा था समायोजन

नगरपालिका बैतूल की चुंगी क्षतिपूर्ति राशि अन्य नगरपालिकाओं के बिजली बिलों में समायोजित की जा रही थी। यह सिलसिला 6-7 माह या उससे अधिक समय से जारी था। नपा सीएमओ सतीश मटसेनिया ने बताया कि मामला सामने आने के बाद पिछले 6-7 महीने के रिकार्ड का अवलोकन किया गया तो पाया कि हर महीने इसी तरह चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि समायोजित हो रही थी। जिसके बाद विभाग को पत्र लिखकर अवगत कराते हुए जांच की मांग की है। नपा द्वारा पत्र में स्पष्ट किया गया है कि बैतूल नगर पालिका को मिलने वाली चुंगी क्षतिपूर्ति राशि का उपयोग नियमों के विपरीत करते हुए दूसरे निकाय के बिजली बिल चुकाने में किया गया, जो वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है।

प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पत्र में यह भी आशंका जताई कि ऐसा समायोजन केवल नवंबर में ही नहीं, बल्कि पूर्व महीनों और वर्षों में भी किया गया हो सकता है। इसलिए प्रकरण की गंभीरता इस बात से भी समझी जा सकती है कि चुंगी क्षतिपूर्ति राशि का उपयोग सफाई व्यवस्था, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, कर्मचारियों के वेतन और शहर के विकास कार्यों में किया जाता है। यदि राशि से दूसरे निकायों के देयकों के भुगतान में समायोजन हो रहा है तो इसका असर बैतूल शहर के विकास कार्यों और सुविधाओं पर पडना तय है।

इनका कहना है -

चुंगी क्षतिपूर्ति राशि से अन्य नगरपालिकाओं के देयकों के भुगतान का मामला सामने आने पर विभाग को पत्र आपत्ति दर्ज कराई है और जांच की मांग की है। पिछले 6-7 माह से यह राशि अन्य नगरपालिकाओं के देयकों के भुगतान में समायोजित की जा रही थी। जिससे प्रतिमाह बैतूल नगरपालिका को 7 से 8 लाख का नुकसान हो रहा था। विभाग को पत्र लिखकर समायोजित राशि लौटाने की मांग की है।

- सतीश मटतेनिया,
सीएमओ नगरपालिका बैतूल

पत्र लिखकर समायोजित राशि लौटाने की मांग

नगर पालिका परिषद बैतूल द्वारा संयुक्त संचालक (वित्त), नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल को भेजे गये पत्र के अनुसार संचालनालय द्वारा प्रतिमाह नियम को चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि प्रदान की जाती है। इस राशि से संबंधित नगरपालिका के विद्युत देयको की कटौती की जाती है। नगरपालिका बैतूल ने अपने पत्र में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से मांग की है कि इस पूरे मामले का विस्तृत परीक्षण कराया जाए। साथ ही समायोजित की गई राशि को संबंधित निकाय से वसूल कर बैतूल नगरपालिका परिषद को लौटाया जाए। इसके अलावा पूर्व में यदि इस प्रकार के समायोजन हुए है तो उनकी भी जांच कर वास्तविक वित्तीय नुकसान का आंकलन किया जाए।

ब्रह्माकुमारीज का वार्षिकोत्सव एवं खेल प्रतियोगिताएं संपन्न

बैतूल। खंजनपुर स्थित प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आनंद सरोवर परिसर में वार्षिकोत्सव का गरिमामय आयोजन किया गया। इस अवसर पर बैतूल सेवा केंद्र प्रभारी ब्रह्माकुमारी मंजू दीदी ने सकारात्मक विचार साझा किए और उपस्थित जनसमूह को श्रेष्ठ एवं खुशहाल जीवन निर्माण के संकल्प कराए। कार्यक्रम के अंतर्गत ब्रह्माकुमारीज के स्पोर्ट्स विंग द्वारा खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया थीम पर आधारित विभिन्न खेल

प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में पूरे जिले ब्रह्माकुमारी परिवार के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। खेल गतिविधियों का उद्देश्य शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक संतुलन और टीम भावना को प्रोत्साहित करना रहा। प्रतियोगिताओं के समापन पर विजेताओं को पुरस्कार एवं मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में केक काट कर वार्षिकोत्सव को उल्लास पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम ने सभी में नववर्ष के प्रति नई ऊर्जा, उत्साह और सकारात्मकता का संचार किया। इस अवसर पर सारणी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता दीदी, बीके मालती दीदी, बीके नंदकिशोर भाई, बीके तरुण भाई सहित सैकड़ों की संख्या में ब्रह्माकुमारीज परिवार के सदस्य उपस्थित रहे।

भीमपुर कॉलेज में सिकल सेल स्क्रीनिंग व रक्त जांच शिविर, बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने कराई जांच

बैतूल। शासकीय महाविद्यालय भीमपुर में सिकल सेल स्क्रीनिंग एवं रक्त जांच शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. बबीता राय द्वारा माता सरस्वती के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। यह शिविर राष्ट्रीय सेवा योजना, क्रीड़ा विभाग एवं स्वामी विवेकानंद प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ, जिसमें विद्यार्थियों एवं स्टाफ ने

उत्साहपूर्वक सहभागिता की। शिविर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भीमपुर से डॉ. कुंवरसिंह आहके, नंदराम सेलुकर, बृजलाल उइके, दया रावत, संतोष यादव, दुशाली कॉमेडे, पारकला नरेकर, सुमंत्री कवडे, रघुवीर उइके एवं विजेश इरपाचे ने सेवाएं दीं। टीम द्वारा बीपी जांच, सिकल सेल स्क्रीनिंग, सीबीसी, हीमोग्लोबिन एवं कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट किए गए। महाविद्यालय की ओर से डॉ. संदीप राने (राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी पुरुष इकाई), डॉ. अभिनित सरसोंदे (क्रीड़ा अधिकारी), डॉ. विजय डढोरे (टीपीओ), डॉ. शोभा बघेल, डॉ. रविकांत पाटील, डॉ. रुचि नंदनवार, अंकित चौरे, दीपक ऊईके, सतीश सोनपुरे, सुनील, मेघराज मोंगरे, राष्ट्रीय सेवा योजना के उमेश काकोडिया, पूर्वा, समस्त स्वयंसेवक छात्र-छात्राएं एवं महाविद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। शिविर के माध्यम से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया।

सिंचाई व्यवस्था सुचारू रहे, किसानों की शिकायतों का जल संसाधन और एमपीईबी गंभीरतापूर्वक निराकरण कराएं

कलेक्टर की अध्यक्षता में समयसीमा की बैठक आयोजित

बैतूल। जिले में रबी सीजन के लिए सिंचाई सुविधा सुचारू रहे। किसानों की सिंचाई और बिजली से संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर गंभीरतापूर्वक निराकरण किया जाएं। यह निर्देश कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित समय सीमा की बैठक में जल संसाधन और एमपीईबी के अधिकारियों को दिए। बैठक में कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने जल संसाधन, जनजातीय कार्य, श्रम, सामाजिक न्याय, वन और नगरीय प्रशासन को शिकायतों के निराकरण में विशेष ध्यान देकर निराकरण किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों को सख्त निर्देशित किया कि अपने अधीनस्थ अमले को फील्ड पर भेजकर विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में गति लाएं। साथ ही विभाग से जुड़ी शिकायतों का भी संतुष्टि पूर्वक समाधान कराएं। बैठक में कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना इत्यादि स्वरोजगार मूलक योजनाओं की समीक्षा कर सभी स्वरोजगार

मूलक योजनाओं में शत प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की समीक्षा कर एमपीपीजीसीएल, एमपीईबी, स्वास्थ्य, पीएचई इतियादी विभागों को योजना में युवाओं के पंजीयन में सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए। प्राचार्य आईटीआई ने बताया कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में अभी तक 51 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की गई, जिसमें प्रगति निरंतर जारी हैं। उन्होंने वन विभाग से जुड़े सभी विभागों के समन्वय बिंदुओं की भी समीक्षा कर निराकरण के निर्देश दिए।

नो मैप मतदाताओं की सुनवाई प्रारंभ-

संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी मकसूद अहमद ने बताया कि निर्वाचन आयोजन के निर्देशों के क्रम में जिले के 6995 नो मैप मतदाताओं की सुनवाई का कार्य आज से प्रारंभ हो गया हैं। सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सुनवाई की जा रही हैं। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने कहा कि नो मैप मतदाताओं की 13 दस्तावेजों पर वन विभाग, शिक्षा विभाग, जनजातीय कार्य विभाग, योजना, लोक सेवा प्रबंधन और ई गवर्नेंस निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भेजे गए इन दस्तावेजों पर सत्यापन रिपोर्ट यथाशीघ्र भिजवाएं। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने मतदाता सूची में नाम जोडने, विलोपन और स्थानांतरित करने के लिए प्राप्त प्रारूप 6, प्रारूप 7 एवं प्रारूप 8 के आवेदनों का समय पर निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अक्षत जैन, अपर कलेक्टर श्रीमती वंदना जाट सहित अन्य सभी विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहें।

संक्षिप्त समाचार

पेयजल पाइपलाइन सहित जलापूर्ति वितरण व्यवस्था का किया निरीक्षण

रायसेन (निप्र)। कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा आज सभी एसडीएम, तहसीलदार, सीएमओ सहित अन्य अधिकारियों को जलापूर्ति प्रणाली की अनुरक्षण व्यवस्था, पाइपलाइन रिसाव पहचान, पेयजल गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिनके परिपालन में अधिकारियों निकायों में विभिन्न वार्डों का भ्रमण कर जलापूर्ति प्रणाली की अनुरक्षण व्यवस्था, पाइपलाइन का निरीक्षण किया जा रहा है। रायसेन में सीएमओ सुरेखा जाटव, तहसीलदार द्वारा अमले के साथ अनेक वार्डों का भ्रमण कर जल वितरण हेतु बिछाई गई पाइपलाइनों का जायजा लिया और नालियों के समीप या उनमें डूबी हुई पाइपलाइनों को शिफ्ट करने के संबंध में निर्देश दिए। इसी प्रकार गैरतगंज और बेगमगंज में भी फिल्टर प्लांट का राजस्व तथा नगरीय निकाय के अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण किया गया। सिलवानी में भी एसडीएम द्वारा सिलवानी तहसील में जलापूर्ति प्रणाली व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की गई। जिले के अन्य निकायों में भी अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा पेयजल वितरण पाइपलाइन सहित जलापूर्ति वितरण प्रणाली, जल शोधन संयंत्र तथा उच्च स्तरीय टंकियों का निरीक्षण किया गया।

विधायक डॉक्टर चौधरी ने ग्राम नागौरी में 3 करोड़ 36 लाख रुपए लागत के सड़क निर्माण कार्य का किया पूजन

रायसेन (निप्र)। विधायक डॉक्टर चौधरी ने ग्राम नागौरी में 3 करोड़ 36 लाख रुपए लागत के सड़क निर्माण कार्य का किया पूजन, पंचायत को वितरित किए टैंकर रायसेन, 02 जनवरी 2026 सांची विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ प्रभुराम चौधरी द्वारा शुक्रवार को सांची क्षेत्र की ग्राम पंचायत ग़ीडगढ़, अम्बाडी एवं कोटरा पंचायतों को पानी के टैंकर वितरित किए गए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जल संकट की स्थिति उत्पन्न होने पर इन टैंकर के माध्यम से जल की आपूर्ति में सुविधा होगी, जिससे ग्रामीणों को राहत मिलेगी। इसके अतिरिक्त ग्राम नागौरी में आयोजित कार्यक्रम में नागौरी से अंजली होटल, साँची कुआँ-नागोरी मार्ग निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया गया। यह सड़क निर्माण परियोजना 3 करोड़ 36 लाख की लागत से पूर्ण की जाएगी, जिससे क्षेत्रवासियों को बेहतर आवागमन सुविधा प्राप्त होगी। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधी और अधिकारी उपस्थित रहे।

जिला प्रशासन द्वारा सभी नगरीय निकायों के फिल्टर प्लांटों का संयुक्त निरीक्षण

विदिशा (निप्र)। जिला प्रशासन द्वारा आज जिले के सभी नगरीय निकायों में संचालित फिल्टर प्लांटों का संयुक्त रूप से निरीक्षण कराया गया। यह निरीक्षण नागरिकों को शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने तथा जल प्रदाय व्यवस्था की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया। संयुक्त निरीक्षण के दौरान फिल्टर प्लांटों में जल शोधन की प्रक्रिया, केमिकल डोजिंग, जल परीक्षण व्यवस्था, मशीनरी की कार्यशील स्थिति, साफ-सफाई एवं संधारण कार्यों की विस्तार से जांच की गई। अधिकारियों द्वारा जल की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप परीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा आवश्यक सुधारात्मक निर्देश भी दिए गए। निरीक्षण के समय जहां-जहां कमियां पाई गईं, वहां संबंधित निकाय अधिकारियों को तत्काल सुधार कार्य करने के निर्देश दिए गए, साथ ही भविष्य में पेयजल की गुणवत्ता प्रभावित न हो इसके लिए नियमित मॉनिटरिंग एवं रख-रखाव सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि पेयजल की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु ऐसे निरीक्षण आगे भी नियमित रूप से जारी रहेंगे।

जिले में नागरिकों को साफ, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं: कलेक्टर

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में एसडीएम, सीएमओ, पीएचई और जल निगम के अधिकारियों को दिए दिशा-निर्देश

रायसेन (निप्र)। जिले में नागरिकों को साफ, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं- कलेक्टर श्री विश्वकर्मा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में एसडीएम, सीएमओ, पीएचई और जल निगम के अधिकारियों को दिए दिशा-निर्देश रायसेन, 03 जनवरी 2026 कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा सभी एसडीएम, तहसीलदार, जनपद पंचायत सीईओ, सीएमओ तथा पीएचई और जल निगम के अधिकारियों को जिले में नागरिकों को साफ, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। उन्होंने जिले में जलापूर्ति प्रणाली की अनुरक्षण व्यवस्था, पाइपलाइन रिसाव पहचान, पेयजल गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए अधिकारियों से कहा कि यह आमजन के स्वास्थ्य से जुड़ा है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही ना हो।

इसके साथ ही जलापूर्ति संबधी शिकायत निवारण तंत्र सुदृढ़ीकरण करते हुए पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाओं के संबंध में फोन या अन्य माध्यम से शिकायत की सूचना मिलने पर तत्काल कदम उठाएं। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने अधिकारियों को शासन द्वारा जारी एसओपी का पालन सुनिश्चत करने के निर्देश देते हुए कहा कि निकायों में बिछाई गई जल वितरण प्रणाली का सात दिवस में सर्वे किया जाकर ऐसे क्षेत्र जहां पर सघन आबादी अथवा 20 वर्ष से अधिक पुरानी पाईपलाईन बिछी हुई है, उनका चिन्हांकन किया जाए। पुरानी एवं बार-बार लीकेज होने वाली पाईपलाईन, नालियों/सीवर पाईपलाईन के समीप अथवा नीचे से गुजरने वाली पाईपलाईनों का भी चिन्हांकन किया जाए। चिन्हांकन में रिसाव पाए जाने पर 48 घण्टे के भीतर मरम्मत सुनिश्चित की जाए।

इसके साथ ही जल शोधन संयंत्र तथा उच्च स्तरीय टंकियों की साफ-सफाई का भी सात दिवस में निराकरण कराएं। बैठक में अधिकारियों को सभी जल शोधन संयंत्रों, प्रमुख जल स्त्रोतों तथा उच्च स्तरीय टंकियों सम्प टेन्कस का तत्काल जल नमूना परीक्षण किया जाए। प्रदूषण पाए जाने पर तत्काल जल आपूर्ति रोकी जाए एवं वैकल्पिक सुरक्षित जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा द्वारा नगरीय क्षेत्र में जल के अन्य स्त्रोतों कुएं, बावड़ी, तालाब तथा नलकूपों में ब्लीचिंग पाउडर निर्धारित मानकों के अनुरूप उपयोग किया जाए।

जल शोधन संयंत्रों एवं जल परीक्षण प्रयोगशालाओं में पर्याप्त मात्रा में आवश्यक रसायन एवं उपकरणों की उपलब्धता रहे। साथ ही क्लोरिनेशन सिस्टम की 24ग7 निगरानी की जाए। इसी प्रकार सभी निकायों में जल शोधन संयंत्रों पर स्थापित लैब, मोबाईल लैब, एनएबीएल अधिकृत लैब, पीएचई विभाग की स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जल परीक्षण प्रयोगशालाओं से जल नमूनों का नियमित अंतराल पर परीक्षण कराया जाए। साथ ही निकाय के बाहरी क्षेत्र की जलप्रदाय व्यवस्था के संबंध में भी समन्वय किया जाए। जल की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप होना चाहिए। सभी नगरीय निकायों में पाईपलाईन लीकेज डिटेक्शन हेतु जनजागरूकता अभियान चलाया जाए। निकायों में वार्डवार कम्यूनिकेशन प्लान तैयार किया जाए जिसमें सीएमओ, जल प्रदाय शाखा के प्रभारी अभियंता, सुपरवाइजर, वॉल्व मेन, पम्प अटैन्डेन्ट के दूरभाष/मोबाईल नम्बर की जानकारी हो जिसे विभाग या निकाय की वेबसाइट, कार्यालयों के सूचना पटल एवं महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किया जाए। जल प्रदाय व्यवस्था सुनिश्चित करने वार्डवार जलप्रदाय शाखा के प्रभारी अभियंता की व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने निर्देश दिए कि जल आपूर्ति से संबंधित प्राप्त शिकायतों को इमर्जेंसी में रखा जाए और लीकेज/दूषित जल शिकायतों का 24 से 48 घंटों के भीतर अनिवार्य रूप से निराकरण किया जाए। सीएम हैल्पलाईन में गंदा/दूषित पेयजल तथा सीवेज से संबंधित प्राप्त शिकायतों के निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री मनोज उपाध्याय, एसडीएम, पीओ डूडा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा जल निगम सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। विकासखण्डों से एसडीएम, जनपद सीईओ, सीएमओ सहित अन्य अधिकारी वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से बैठक में उपस्थित रहे।

मक्का के भुट्टों के भूसे की उपलब्धता गौवंश के पोषण हेतु महत्वपूर्ण पहल

विदिशा (निप्र)। कुरवाई तहसील के ग्राम सरकंडी पठार, ग्राम पंचायत काछी कुम्हारिया स्थित कामदगिरि गौशाला में गौवंश के पोषण एवं चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मक्का के भुट्टों का भूसा उपलब्ध कराया गया। मक्का भुट्टों से प्राप्त यह भूसा पशुओं के लिए पौष्टिक चारे के रूप में उपयोगी है, जिससे गौवंश के स्वास्थ्य एवं दुग्ध उत्पादन में सहायक लाभ मिलता है। गौशाला प्रबंधन द्वारा बताया गया कि मक्का भुट्टों का भूसा आसानी से पचने योग्य होता है तथा यह गौवंश को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। इससे सर्दी एवं ग्रीष्म दोनों मौसम में पशुओं को संतुलित आहार उपलब्ध कराने में मदद मिलती है। ग्राम पंचायत काछी कुम्हारिया एवं गौशाला समिति के सहयोग से चारा प्रबंधन की यह व्यवस्था की गई है, जिससे गौशाला में आश्रयित पशुओं को नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण आहार मिल सके। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कृषि अवशेषों के सदुपयोग से न केवल गौवंश का संरक्षण हो रहा है, बल्कि किसानों को भी अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो रहा है। गौशाला प्रबंधन ने बताया कि भविष्य में भी इसी प्रकार विभिन्न स्रोतों से चारे की व्यवस्था कर गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सतत प्रयास किए जाते रहेंगे।

रायसेन से रेस्क्यू किए थे, अब चूरना के जंगल में छोड़ा, कॉलर आईडी से होगी निगरानी

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 8 महीने बाद 2 बाघ आजाद

नर्मदापुरम (निप्र)। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व (एसटीआर) के मालनी बाड़े में 8 महीने से कैद दो बाघों को शुक्रवार शाम आजादी मिल गई। एसटीआर प्रबंधन ने दोनों भाइयों को चूरना के जंगल में खुले में छोड़ दिया है, ताकि वे अपना खुद का इलाका (टेरिटरी) बना सकें। जंगल में छोड़ने से पहले दोनों बाघों को कॉलर आईडी लगाई गई है, जिससे उनकी मूवमेंट की मॉनिटरिंग की जाएगी। ये दोनों बाघ मार्च 2025 में रायसेन के भोजपुर के पास अपनी मां से बिछड़ गए थे।

मां से बिछड़े थे, इसलिए बाड़े में शिकार करना सिखाया : फील्ड डायरेक्टर राखी नंदा ने बताया कि दोनों बाघों की उम्र अभी 2 साल है। 9 महीने पहले जब वे अपनी मां से बिछड़े थे, तब उनकी उम्र 14-15 महीने थी। जंगल में सर्वाइव करने के लिए जो चीजें उन्हें मां से सीखनी चाहिए थीं, वे बिछड़ने के कारण सीख नहीं पाए थे। इसलिए उन्हें रेस्क्यू कर मालनी स्थित बाड़े में रखा गया। यहां पिछले 8 महीनों तक एसटीआर प्रबंधन की देखरेख में उन्हें शिकार की बारीकियां सिखाई गईं।

पिंजरा खुलते ही दहाड़ते हुए भागे : बाघों को जंगल में छोड़ते समय फील्ड डायरेक्टर राखी नंदा, डिप्टी डायरेक्टर ऋषभा नेताम, सहायक संचालक विनोद वर्मा, रेंजर आरपी पाठक और वन्यप्राणी डॉक्टर गुरुदत्त शर्मा मौजूद रहे। टीम उन्हें बाड़े से पिंजरे में रखकर घने जंगल में लेकर पहुंची। जैसे ही पिंजरे का गेट खोला गया, कुछ देर तक बाघ पिंजरे में ही खड़े रहे। इसके बाद दहाड़ते हुए पिंजरे से कूदकर जंगल की ओर भाग गए।

मवेशियों का शिकार कर रहे थे, इसलिए किया था रेस्क्यू : रायसेन की भोजपुर रेंज में मार्च 2025 में ये दोनों बाघ अपनी मां (बाघिन) से अलग हो गए थे। उस समय भूख मिटाने के लिए वे पालतू मवेशियों का शिकार कर रहे थे। इससे ग्रामीणों को परेशानी हो रही थी और वे डर के कारण अपनी फसलें नहीं काट पा रहे थे। इसी समस्या को देखते हुए वन विभाग ने उन्हें रेस्क्यू किया और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के मालनी बाड़े में शिफ्ट किया था।

कृषि विभाग की योजनाओं में एग्रीस्टेक का उपयोग अनिवार्य

जिले में अब तक 2.65 लाख से अधिक फार्मर आईडी तैयार

बैतूल (निप्र)। भारत सरकार द्वारा विकसित एग्रीस्टेकएक समग्र डिजिटल इकोसिस्टम है, जिसका उद्देश्य किसानों के लिए एक केंद्रीकृत डेटाबेस तैयार करना है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों की पहचान, भूमि अभिलेख, फसल विवरण जैसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ एकीकृत की जाती हैं, ताकि उन्हें ऋण, वैज्ञानिक सलाह, गुणवत्तापूर्ण बीज, बाजार तक पहुंच तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ सरलता से मिल सके। एग्रीस्टेक से कृषि मूल्य श्रृंखला को डिजिटल रूप से सशक्त करने के साथ-साथ कृषक हितेषी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और दक्षता भी सुनिश्चित होगी। भारत सरकार के एग्रीस्टेक कार्यक्रम को प्रदेश में भी प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। केंद्र की अपेक्षाओं के अनुरूप फार्मर आईडी निर्माण तथा डिजिटल क्रॉप सर्वे में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। जिले में अब तक 2.65 लाख से अधिक फार्मर आईडी तैयार की जा चुकी हैं। कृषि विभाग द्वारा प्रमुख कृषक-उन्मुख योजनाओं के हितग्राही घटकों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराते हुए एग्रीस्टेक से एकीकृत किया जा रहा है, जिससे किसानों को अपने गांव या मोबाइल फोन पर ही योजनाओं की जानकारी मिलेगी और बिना किसी कागजी कार्यवाही के आवेदन की सुविधा उपलब्ध होगी। इसी क्रम में शासन द्वारा खरीफ 2026 से सभी विभागीय हितग्राही मूलक कृषक-उन्मुख योजनाओं में सहायता/अनुदान के लिए फार्मर आईडी को अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत जिले में शत-प्रतिशत पात्र कृषकों की फार्मर आईडी बनाए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है, ताकि आगामी खरीफ मौसम से सभी योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी रूप से किसानों तक पहुंचाया जा सके।

दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का द्वितीय चरण सफलतापूर्वक संपन्न

बैतूल (निप्र)। कलेक्टर बैतूल श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देशानुसार जिले में 17 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 'दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान 'का द्वितीय चरण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अभियान के अंतर्गत जिले के 14,640 पशुपालकों के घर-घर जाकर पशुपालन विभाग के विशेषज्ञों द्वारा पशुपालन से संबंधित आवश्यक एवं उपयोगी जानकारी प्रदान की गई। उप संचालक पशुपालन श्री सुरजीत सिंह ने बताया कि अभियान का उद्देश्य दुग्ध उत्पादन में गुणात्मक सुधार लाना है। इसके लिए पशुपालकों को तीन प्रमुख स्तंभों–नस्ल सुधार, पशु पोषण एवं पशु स्वास्थ्य–पर व्यापक रूप से जागरूक किया गया। पशु स्वास्थ्य के अंतर्गत सभी आवश्यक टीकाकरण कार्यों की जानकारी दी गई, वहीं पशु पोषण में कृमिनाशक औषधियों के उपयोग से पशुओं के पेट में मौजूद कृमियों के नाश पर बल दिया गया। साथ ही हरा चारा जैसे नेपियर घास, साइलेज, ज्वार, मक्का, चरी, बरसीम एवं लूसर्न खिलाने से दुधारू पशुओं के दूध उत्पादन में वृद्धि होने की जानकारी दी गई। अभियान के दौरान पशुपालकों को बताया गया कि नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में सेक्स्ड सॉर्टेड सीमन उपलब्ध है। पशुपालकों से अनुरोध किया गया कि वे इसी सीमन से नस्लवार कृत्रिम गर्भाधान कराएं। इससे नस्ल सुधार के साथ-साथ दुग्ध उत्पादन में भी वृद्धि होती है और पशुपालकों को आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। उप संचालक डॉ. सुरजीत सिंह द्वारा पशुपालकों से संवाद के दौरान पशु नस्ल सुधार, पोषण, स्वास्थ्य एवं उससे होने वाले आर्थिक लाभों पर विस्तार से समझाइश दी गई। इस अवसर पर प्रगतिशील पशुपालक श्री दिनेश खाडे भी निरीक्षण दल के साथ उपस्थित रहे। उन्होंने गृह भेंट के दौरान उन्नत पशुपालन से आय एवं लाभ अर्जन के तरीकों पर पशुपालकों को प्रेरित किया। यह अभियान जिले में पशुपालन को सशक्त बनाने एवं पशुपालकों की आय बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ।

विजयवर्गीय ने इस्तीफा नहीं दिया तो महाआंदोलन करेगी कांग्रेस

नर्मदापुरम में पीसीसी चीफ पटवारी बोले- 11 जनवरी तक मंत्री, महापौर पर एफआईआर भी हो

नर्मदापुरम (निप्र)। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से 14 लोगों की मौत और 200 से ज्यादा के बीमार होने की घटना के खिलाफ नर्मदापुरम कांग्रेस अब आंदोलन करेगी। 11 जनवरी से कांग्रेस पार्टी मप्र स्तर का महाआंदोलन करने की तैयारी में है। अगर 11 जनवरी के पहले नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा और जिम्मेदार अधिकारी, महापौर पर एफआईआर नहीं होती है तो कांग्रेस धरने पर बैठेगी। यह ऐलान स्वयं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शनिवार को नर्मदापुरम में मीडिया से बातचीत में कहा। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी कांग्रेस के संगठन सृजन के तहत 'बूथ चलो, गांव चलो' अभियान के अंतर्गत नर्मदापुरम के ग्राम निमसाड़िया पहुंचे थे। यहां पर ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन किया। पटवारी ने कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए, इसके बारे में सभी को बताया। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में किस प्रकार हमें काम करना है, इस पर जोर दिया।

एक जान की कीमत 2 लाख, अफसरों का केवल ट्रांसफर

पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा 11 जनवरी संबंधितों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी हजारों लोगों के साथ इंदौर में महाआंदोलन करेगी। पटवारी ने कहा ये नहीं चल सकता कि लोग मरते रहें और अधिकारी मौन रहें। अधिकारियों के ट्रांसफर, सस्पेंड करके लोगों की आंखों में धूल झोंक कर 2 लाख जान की कीमत लगाना गलत है। मोहन यादव सरकार ने एक जान के बदले 2 लाख का मुआवजा दिया और चार अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया। उन्होंने कहा प्रदेश की एक पंचायत में सरकारी अधिकारी मात्र दो घंटे में डेढ़ लाख के ड्रायफ्रूट्स खा गए और यहां एक जान की कीमत मात्र 2 लाख रुपए। किस तरीके का मप्र बना रहे हैं

मौतें होती, पर कठोर कार्रवाई नहीं, इस्तीफा देना होगा

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा इससे पहले 26 बच्चों की मौत दवा पीने से हुई, कुएं में गिरकर 36 मौतें, किसी पर कार्रवाई नहीं। उससे पहले अस्पताल में चूहों ने नोचकर बच्चों को मार डाला। किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। मंत्रियों को अपनी जवाबदारी लेनी पड़ेगी। कैलाश विजयवर्गीय को इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी 11 जनवरी को इंदौर में मप्र स्तर का महाआंदोलन करेगी।

आरओ वाटर सप्लायर्स से पानी के नमूने लिए

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के निर्देशानुसार जिले में संचालित आर ओ वाटर प्लांट का निरीक्षण किया जा रहा है। आज शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा, शेरपुर स्थित शान्ति जलधारा तथा श्रीराम वाटर सप्लायर का निरीक्षण किया तथा उक्त दोनों वाटर सप्लायर से पानी के नमूने जांच हेतु एकत्रित किए गए है। तथा सांची रोड स्थित नन्हा चाह का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थ गुड, मसाला चाय के नमूने एकत्रित किए गए। उक्त नमूने राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजे गए है। इसी प्रकार 30दिसंबर 2025 को भी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम द्वारा बैस नगर स्थित मां घंटियाली पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का निरीक्षण किया तथा पैकेज ड्रिंकिंग वाटर ब्रांड आइकन के दो नमूने जांच हेतु एकत्रित किए गए हैं।

मप्र 22वें से 6वें स्थान पर पहुंचा

एक साल में मप्र के लोगों से 581 करोड़ ठग ले गए जालसाज

भोपाल। मप्र में साइबर ठगी के लगातार बढ़ते दायरे के बीच वर्ष 2025 में जालसाजों ने 55659 लोगों के साथ साइबर फ्रॉड कर दिया है। ठगी के इन मामलों में प्रदेश के लोगों से कुल 581 करोड़ रुपए की ठगी की गई। हालांकि, एक पहलू यह भी है कि इन शिकायतों पर पुलिस की ओर से समय रहते हुई तकनीकी कार्रवाई के कारण 137 करोड़ रुपए से ज्यादा ठगी गई राशि को होल्ड भी करवा दी है।

इसके साथ साइबर फ्रॉड की रकम फ्रीज कराने के मामले में प्रदेश ने देश में 22वें स्थान से छलांग लगाकर 6वां स्थान हासिल किया है। वर्ष 2024 में सायबर वित्तीय फ्रॉड से संबंधित 58,643 शिकायतें मिली थीं। इनमें ठगी की राशि में से करीब 47 करोड़ रुपए ही होल्ड करवाए जा सके थे। राज्य साइबर पुलिस के अनुसार लगातार निगरानी, बैंकिंग सिस्टम से बेहतर समन्वय और विशेष साइबर इकाइयों की सक्रियता का नतीजा है कि 2025 में होल्ड की गई राशि में करीब 191 प्रतिशत बढ़ोतरी दर्ज की गई।

जागरूकता अभियानों और कार्यक्रमों से बदले हालात

मप्र साइबर पुलिस ने वर्ष 2017 से 2025 के बीच 26,200 से ज्यादा ऑनलाइन व ऑफलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनके जरिए 21 करोड़ से ज्यादा लोगों को साइबर अपराधों के प्रति सचेत किया गया। फरवरी 2025 में पूरे प्रदेश में "SAFE CLICK" साइबर अवेयरनेस अभियान चलाया गया, जिसके तहत भौतिक रूप से 13 लाख से ज्यादा और डिजिटल माध्यम से 20 लाख से ज्यादा लोगों को जागरूक किया गया। इस तरह कुल 33 लाख से अधिक लोग अभियान से जुड़ चुके हैं।

एक पहलू यह भी...1930 साइबर हेल्पलाइन को किया मजबूत

वित्तीय साइबर फ्रॉड की रोकथाम के लिए डायल-100/112 से समन्वय कर संचालित 1930 साइबर हेल्पलाइन को मजबूत किया गया है। साइबर मुख्यालय और जोनल कार्यालयों में 15 सदस्यीय कुल 5 टीमें, तैनात हैं। वर्ष 2025 में 1930 (एनसीआरपी) के जरिए 55,659 शिकायतें दर्ज हुई

4 सदस्यीय टीम तैनात, रियल टाइम फ्रॉड रोकने की व्यवस्था

फ्रॉड की रकम को तुरंत रोकने और पीड़ितों को राहत दिलाने के लिए साइबर मुख्यालय द्वारा एससीएफएमसी का गठन कर चार सदस्यीय टीम को तैनात किया गया है। इसके अलावा आई4सी, नई दिल्ली स्थित साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर में मप्र साइबर पुलिस के अफसर को पदस्थ कर बैंक और अन्य एजेंसियों से समन्वय के जरिए फ्रॉड की राशि रोकने की कार्रवाई की जा रही है।

जिला स्तर पर टास्क फोर्स का गठन और विशेष ऑपरेशन- साइबर अपराधों के तेजी से बढ़ते दायरे को देखते हुए जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षकों के अधीन जिला साइबर टास्क फोर्स के गठन किया गया है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले साइबर अपराधों पर रोक के लिए ऑपरेशन NAYAN चलाया गया, जिसके तहत दर्ज 50 मामलों में करीब 40 आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई।

संक्रांत पर खत्म हो सकता है इंतजार!

भाजपा के गलियारों में उन नेताओं की धड़कनें तेज हैं, जो लंबे समय से पद की आस में बैठे हैं। चर्चा है कि मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मोहन सरकार निगम-मंडलों के खाली पड़े पदों पर

मोहन का मंत्रालय

आशीष चौधरी

नियुक्तियों की सौगात दे सकती है। मुख्यमंत्री के 18 जनवरी को प्रस्तावित विदेश प्रवास से पहले इन नामों पर मुहर लगने की प्रबल संभावना है। नामों पर लगभग सहमति बन गयी है और केंद्रीय नेतत्व से मोहर भी। लंबे समय से 'बेरोजगार' बैठे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि इस बार उनकी पतंग पद के आसमान में जरूर उड़ेगी।

रिटायर्ड 'साहब' की नर्मदा परिक्रमा

प्रदेश के प्रशासनिक हलकों में एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी इन दिनों सुर्खियों में हैं। चर्चा है कि 'प्रमोटेड' कोटे से आए ये पूर्व साहब इन दिनों मां नर्मदा की परिक्रमा पर सपत्नीक निकल पड़े हैं। परिक्रमा की शुरुआत नर्मदा अंचल हो चुकी है और संकल्प समापन तक का है। ब्यूरोक्रेसी और राजनीति में अब इस यात्रा के निहितार्थ खोजे जा रहे हैं। क्या यह केवल आत्मिक शांति के लिए है, या फिर भविष्य की किसी बड़ी राजनीतिक पारी की तैयारी? हालांकि 'साहब' ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन उनकी यह यात्रा चर्चाओं का केंद्र बनी हुई है।

रहस्यमयी चुप्पी

इंदौर का 'जहरीला जल कांड' शहर के लिए त्रासदी बन गया है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि हर मुद्दे पर मुखर रहने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने इस मामले पर 'मौन व्रत' धारण कर लिया है। राजनीतिक गलियारों में यह चुप्पी चर्चा का विषय है। पंडितों का कहना है कि जो नेता छोटी-छोटी प्रशासनिक चूक पर सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ते, वे इतनी बड़ी घटना पर क्यों खामोश हैं? क्या यह चुप्पी खास आत्मीय रिश्ते की वजह से है। वैसे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का इंदौर से बड़ा करीबी संबंध रहा है और भाजपा के नेताओं से भी उनके अच्छे संबंध है। पिछले दिनों एक फोटो भी राजनीति में कभी चर्चा का विषय बनी थी। फिलहाल, इस रहस्यमयी खामोशी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

साहब का 'सत्कारी' निरीक्षण

पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियरों की टोली जब लाव-लश्कर के साथ 'सड़क नापने' निकली, तो इंजीनियरिंग के नए आयाम स्थापित हो गए। साहब की पारखी नजरों ने अपने 'चहेते' इंजीनियरों की उन सड़कों में भी मखमली अहसास ढूंढ लिया, जहाँ गिट्टियाँ अभी से हिचकियाँ ले रही थीं। आखिर जिस सड़क पर साहब का 'शाही सत्कार' और काजू-किशमिश का प्रबंध पुख्ता हो, उसकी गुणवत्ता पर शक करना पाप है! जिन इंजीनियरों से साहब की 'पटरी' नहीं बैठती, उनकी शानदार सड़कों में भी उन्हें भ्रष्टाचार के गड्ढे नजर आ गए। कसूर सड़क का नहीं, साहब के 'स्वाद' का था जो वहां फीका रह गया। वाकई, पीडब्ल्यूडी की सड़कों की मजबूती डामर से नहीं, साहब की आवभगत की 'चाशनी' से तय होती है। धन्य है यह निरीक्षण तकनीक! निरीक्षण रिपोर्ट अभी आना है

ठंड और पॉल्यूशन का असर, अस्पतालों में इलाज के लिए लंबी कतारें

भोपाल। राजधानी समेत मध्यप्रदेश में घना कोहरा और तेज ठंड का मौसम बना हुआ। भोपाल में चारों ओर धूल की समस्या बनी हुई है। इसके अलावा AQI भी 230 तक पहुंच रहा है। यह सभी फैक्टर मिलकर इस बार के वायरल को मजबूत बना रहे हैं। जिसकी वजह से कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग बार बार सर्दी-खांसी, जुकाम, बुखार के साथ सांस फूलने और सीने में जकड़न की समस्या से ग्रसित हो रहे हैं। जेपी अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार, बीते सालों की तुलना में इस साल ठंड में एलर्जिक राइनाइटिस के केस दो गुना ज्यादा सामने आ रहे हैं। इसकी बड़ी वजह पॉल्यूशन और धूल है। जेपी अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. पियु पंचरत्न ने कहा कि मौजूदा वायरस पहले के मुकाबले ज्यादा ताकतवर है, इसलिए बच्चों को ठंड से बचाकर रखना बेहद जरूरी है। अगर इसके बावजूद ठंड या वायरल से जुड़ी कोई परेशानी नजर आए, तो बिना देर किए नजदीकी डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उनकी सलाह के अनुसार इलाज शुरू करना चाहिए।

ठंड में सांस की दिक्कत क्यों बढ़ी

इस समस्या को एयर पॉल्यूशन और गंभीर बना देता है। खासकर सुबह और शाम के समय जब प्रदूषण का स्तर ज्यादा होता है, तब बाहर निकलने पर सांस से जुड़ी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। अस्पतालों में सबसे ज्यादा 50 से 60 साल से ऊपर के मरीज पहुंच रहे हैं। खासकर वे लोग, जिन्हें पहले से अस्थमा, सीओपीडी या दिल से जुड़ी बीमारी है। बुजुर्गों में ठंड और प्रदूषण दोनों मिलकर परेशानी बढ़ा रहे हैं। बच्चों में भी सर्दी-खांसी और सांस की हल्की दिक्कत के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन गंभीर मरीजों में बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है।

पॉल्यूशन से हालात गंभीर, बुजुर्ग मरीज ज्यादा परेशान

सर्दी बढ़ते ही अस्पतालों की ओपीडी में दिल और सांस से जुड़ी शिकायतों के मरीज 30 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं। पहले हमीदिया अस्पताल की ओपीडी में 150 के करीब ह्रदय रोगी पहुंच रहे थे। अब यह संख्या बढ़कर 200 के करीब पहुंच गई है। डॉक्टरों के अनुसार, ज्यादातर मरीजों में सर्दी-खांसी, जुकाम, बुखार के साथ सांस फूलने और सीने में जकड़न की समस्या शुरुआती लक्षण के रूप में नजर आ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ठंड का असर सीधे फेफड़ों और दिल पर पड़ता है। जेपी अस्पताल के श्वांस रोग विशेषज्ञ डॉ. नवीन शर्मा ने बताया कि ठंडी हवा जब नाक के रास्ते फेफड़ों तक पहुंचती है, तो वह सांस की नलियां सिकुड़ कर सकरी हो जाती हैं। इसे मेडिकल भाषा में ब्रोन्कोकन्सट्रिक्शन कहा जाता है।

26 साल के इंजीनियर की कार्डियक अरेस्ट से मौत

भोपाल। भोपाल के 26 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मसूरी में कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। रविवार को शव को परिजन के सुपुर्द कर दिया गया। हर्ष बिजौरे अपनी बड़ी बहन के बाद परिवार का इकलौता बेटा था। वह करीब तीन साल से दिल्ली से सटे गुरुग्राम में रहकर प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था।

हर्ष, मृतक

नए साल में वह अपने दोस्त और दो महिला मित्रों के साथ मसूरी घूमने गया था। वहां बर्थडे पार्टी के बाद अपने रूम में सोया और फिर सुबह नहीं उठा। पिता जितेंद्र बिजौरे रानी कमलापति स्टेशन पर टिकट रिजर्वेशन डिपार्टमेंट में हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि दिसंबर महीने में हर्ष ने जॉब से रिजाइन दे दिया था। नए साल में नई जॉब करने का संकल्प उसने पहले से ले रखा था। 30 दिसंबर तक उसने नौकरी की। 1 जनवरी को कंपनी में साथ काम करने वाली महिला मित्रों और एक युवक के साथ मसूरी घूमने गया था।

दोस्त विशाल ने दी थी पुलिस को सूचना

मसूरी पुलिस की शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि हर्ष बिजौरे विशाल कुमार, स्वाति और भावना वर्मा के साथ 1 जनवरी 2026 को मसूरी आया था। दोस्त भावना वर्मा का जन्मदिन था, जिसे सभी ने साथ में मनाया। बर्थडे पार्टी के बाद हर्ष रात करीब 11 बजे अपने रूम नंबर-102 में सोने चला गया था। अगले दिन 3 जनवरी की सुबह दोस्त विशाल नाश्ता लेकर उसे उठाने उसके कमरे में गया, तो पाया कि हर्ष की बॉडी ठंडी पड़ी थी और कोई हलचल नहीं थी। विशाल ने इसकी सूचना डॉयल 112 पर दी थी।

दिग्विजय सिंह ने किया मनरेगा का नाम बदलने का विरोध

योजना में गरीबों और मजदूरों का ध्यान नहीं रखा, सीहोर में पदयात्रा का दूसरा दिन

सीहोर। राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह लगातार दूसरे दिन सीहोर जिले के दौरे पर रहे। इच्छावर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खेरी पहुंचे दिग्विजय सिंह ने मनरेगा श्रमिकों से संवाद किया और केंद्र सरकार के नए कानून को लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा।

मनरेगा श्रमिकों से संवाद, कानून पर उठाए सवाल- ग्राम खेरी में दिग्विजय सिंह ने मनरेगा मजदूरों से काफी देर तक बातचीत की। संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा मजदूर और किसानों की लड़ाई लड़ती रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो नया कानून बनाया है, उसमें गरीबों और मजदूरों का ध्यान नहीं रखा गया है।

कांग्रेस मजदूरों के साथ खड़ी रहेगी: दिग्विजय- दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस की यह मुहिम आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नए कानून के तहत ज्यादा से ज्यादा काम मिल सके, इसके लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे और मजदूरों की आवाज को मजबूती से उठाया जाएगा।

घर-घर जाकर सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं

खेरी गांव में रात्रि विश्राम के बाद सोमवार सुबह दिग्विजय सिंह पैदल गांव की गलियों में निकले। उन्होंने घर-घर जाकर ग्रामीणों से बातचीत की। ग्रामीणों ने पानी, सड़क, जलभराव, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और रोजगार से जुड़ी समस्याएं उनके सामने रखीं। यह दौरा कांग्रेस के जमीनी स्तर पर संपर्क और संगठन को मजबूत करने की पहल के तौर पर देखा जा रहा है।

पचमढ़ी में सीट पर बर्फ जमी

नौगांव में पारा 1 डिग्री

बड़वानी में कोहरे में दूध टैंकर पलटा, एक की मौत; 20 जिलों में स्कूलों की छुट्टी

भोपाल। पिछले 3 दिन से पूरा मध्य प्रदेश कोहरे की आगोश में है। भोपाल में सुबह 6 से 7 बजे के बीच इतना घना कोहरा था कि 20 मीटर बाद कुछ दिखाई नहीं दिया। सुबह 11 बजे तक कोहरा छाया रहा। पचमढ़ी में गाड़ियों की सीट पर बर्फ की परत जमी मिली। छतरपुर का नौगांव सबसे ठंडा रहा। यहां सोमवार को तापमान 1 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। खजुराहो, गुना, नर्मदापुरम, रायसेन, दमोह, सागर, जबलपुर, नौगांव, दतिया, धार, ग्वालियर, इंदौर, राजगढ़, रतलाम, उज्जैन, रीवा, सतना, श्योपुर, बालाघाट, उमरिया, सीधी, मंडला, छिंदवाड़ा समेत कई जिलों में कोहरे का असर देखा गया। कोहरे की वजह से बड़वानी जिले में सोमवार सुबह सांची दूध का टैंकर पलट गया। हादसे में हेल्पर कन्हैयालाल मुजाल्दे (35) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ड्राइवर अमजद अहमद शेख (35) गंभीर रूप से घायल हो गया। उधर, सर्दी के तेवरों को देखते हुए नर्मदापुरम में भी 6 और 7 जनवरी को कक्षा 8वीं तक की स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है।

इंदौर आने वाली 10 से ज्यादा उड़ानें घंटों लेट

इंदौर में बदले मौसम और घने कोहरे ने लगातार तीसरे दिन भी हवाई यातायात को बुरी तरह प्रभावित किया। सोमवार सुबह घने कोहरे के कारण इंदौर एयरपोर्ट पर पहला विमान सुबह 8.54 बजे लैंड हो सका, जबकि सामान्य स्थिति में पहली फ्लाइट सुबह 6:40 बजे लैंड होती है। कोहरे के चलते सुबह की 10 से ज्यादा उड़ानें एक से तीन घंटे की देरी से संचालित हुईं।

दिल्ली से आने वाली ट्रेनों की टाइमिंग पर असर

वहीं, दिल्ली से आने वाली ट्रेनों की टाइमिंग पर असर पड़ा है। मालवा, सचखंड, शताब्दी समेत कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से लेट चल रही हैं। मालवा एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 3 घंटे से ज्यादा देरी से चल रही है। सर्द हवाओं की वजह से सर्दी भी तेज हो गई है। ज्यादातर जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे आ गया है। दतिया में 4.4 डिग्री, राजगढ़-खजुराहो में 5.4 डिग्री, मलाजखंड में 5.5 डिग्री, उमरिया में 5.7 डिग्री, मंडला-पचमढ़ी में 5.8 डिग्री दर्ज किया गया। बड़े शहरों में भोपाल में 6.8 डिग्री, इंदौर में 8.6 डिग्री, ग्वालियर में 6.4 डिग्री, उज्जैन में 9.5 डिग्री और जबलपुर में 9 डिग्री रहा।

दूषित पानी की दहशत, इंदौर से घर लौट रहे छात्र

हेपेटाइटिस-ए से पीड़ित वापस आया छात्र, जबलपुर में आईसीयू में भर्ती

जबलपुर। इंदौर में दूषित पानी से हो रही मौतों की खबरों ने लोगों में इस कदर दहशत फैला दी है कि छात्र और कामकाजी लोग इंदौर छोड़कर अपने-अपने घर लौटने लगे हैं। इसी कड़ी में सिवनी जिले के रहने वाले 18 वर्षीय युवक आदित्य मिश्रा की तबीयत बिगड़ने के बाद परिजन उसे इलाज के लिए जबलपुर ले आए, जहां निजी अस्पताल में उसका इलाज जारी है। जांच में आदित्य हेपेटाइटिस-A पॉजिटिव पाया गया है, जिसके चलते उसे डॉक्टरों की निगरानी में आईसीयू वार्ड में रखा गया है।

आदित्य मिश्रा इंदौर के भंवरकुआं क्षेत्र स्थित एक कोचिंग संस्थान से बीबीए की पढ़ाई कर रहा था। वह किराए के कमरे में अकेला रहता था और सार्वजनिक नल से पानी भरकर पीता था। इसी दौरान आदित्य और उसके दो-तीन दोस्त एक साथ बीमार पड़ गए। आदित्य के अन्य साथी अपने-अपने घर लौट गए, जबकि आदित्य ट्रेकिंग के लिए देहरादून चला गया।

ट्रेनिंग के दौरान देहरादून में बिगड़ी तबीयत

परिजनों के अनुसार देहरादून में अचानक आदित्य को चक्कर आया और वह गिर पड़ा। उसकी नाक से खून बहने लगा। साथ गए टीचर और दोस्तों ने उसे घर लौटने की सलाह दी। इसके बाद दिल्ली के एक अस्पताल में जांच कराई गई, जहां डॉक्टरों ने भर्ती होने की सलाह दी, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह परिजनों को सूचना देकर जबलपुर आ गया।

डॉक्टरों ने दूषित पानी को बताया बीमारी का कारण

सरकारी विभाग में पदस्थ आदित्य के पिता राजेश मिश्रा ने बताया कि जब बेटा जबलपुर पहुंचा, तब उसकी हालत बेहद गंभीर थी। तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच में डेंगू रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन प्लेटलेट्स मात्र 17 हजार पाए गए। दांतों से लगातार ब्लीडिंग हो रही थी, हाथ-पैर कांप रहे थे। प्रारंभिक जांच में डॉक्टरों ने दूषित पानी को बीमारी का मुख्य कारण बताया है।

राजेश मिश्रा ने बताया कि फिलहाल इलाज के बाद आदित्य की स्थिति पहले से बेहतर है। उन्होंने इंदौर में रह रहे सभी छात्रों से अपील की है कि वे अपनी सेहत को लेकर बेहद सतर्क रहें, पेयजल के लिए आरओ का उपयोग करें और सार्वजनिक नलों के पानी पर निर्भर न रहें।